@saahassamachar @saahassamachar @saahassamachar

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय संस्करण

साहस समाचार

निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक



अनन्या ने शनाया को किया बर्थडे विश...पेज-8

नई दिल्ली, मंगलवार, 3 नवंबर 2026, वर्ष-2, अंक-16, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए RNI No-DLHIN/25/A2841 www.saahassamachar.in

दिल्ली-एनसीआर में 7-8 नवंबर को सुबह 6-7 बजे तथा रात 8-10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई

दिल्ली-एनसीआर में दीवाली पर फोड़ सकेंगे ग्रीन पटाखे

नई दिल्ली,एजेंसी।

दीपावली से कुछ दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 7 और 8 नवंबर को सुबह छह से सात बजे तथा रात आठ से दस बजे तक हरित पटाखे चलाने की अनुमति दे दी है।

इस वर्ष दीपावली का पर्व आठ नवंबर को मनाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए उपायों और अपने पूर्व के निर्देशों के लागू नहीं होने पर नाराजगी जताई।

पीठ ने कहा कि पटाखे चलाने से निश्चित रूप से प्रदूषण होगा।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष प्रथा का पालन करने का अधिकार, भले ही उसका धार्मिक स्वरूप हो, असीमित नहीं है और इसे संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों की सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। पीठ ने 29 अक्टूबर को यह आदेश दिया था, जिसकी प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई।

पीठ ने कहा, पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना हालांकि सबसे उपयुक्त समाधान प्रतीत होता है, लेकिन हमारा मानना है कि फिलहाल इस अदालत के पास यह तय करने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि पटाखे चलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाना सबसे बेहतर विकल्प होगा या नहीं। न्यायालय ने 15 अक्टूबर, 2025 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें दीपावली के दौरान दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और इन्हें चलाने की अनुमति दी गई थी। इस आदेश में परंपराओं के साथ-साथ पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई थीं।

इसने कहा, पटाखे चलाने की अनुमति इस अदालत द्वारा 15 अक्टूबर, 2025 को पारित आदेश के अनुरूप ही दी जा रही है। तदनुसार, अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि 7 और 8 नवंबर, 2026 को केवल सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाने की अनुमति हो। पीठ ने कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि पटाखों पर पहले की तरह पूर्ण प्रतिबंध 9 नवंबर, 2026 से फिर से लागू हो जाएगा।

न्यायालय ने पटाखों पर प्रतिबंध से संबंधित मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। पीठ ने निर्देश दिया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा अधिसूचित ध्वनि निषेध क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। इसने कहा कि इन क्षेत्रों को 'पटाखा-मुक्त क्षेत्र' घोषित किया जाएगा और इनके बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी प्रकाशित की जाएगी। पीठ ने कहा, यही प्रतिबंध शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होगा। सभी आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इन निर्देशों का उचित रूप से पालन सुनिश्चित हो सके। साथ ही, यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। न्यायालय ने पटाखा निर्माताओं और कारोबारियों के संबंध में भी निर्देश जारी किए। इसने कहा, सीएसआईआर-एनईईआरआई और पीईएसओ (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) द्वारा प्रमाणित पटाखा निर्माताओं को उन हरित पटाखों के निर्माण की ही अनुमति होगी, जिनकी जानकारी दो नवंबर, 2026 से छह नवंबर, 2026 के बीच सीएसआईआर-एनईईआरआई की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।



दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-2 लागू

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के दूसरे चरण को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। सीएक्यूएम ने यह फैसला सोमवार को आयोग की ग्रैप उप-समिति की बैठक में दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में तेजी से हुई वृद्धि और आने वाले दिनों में स्थिति और खराब रहने के पूर्वानुमान के मद्देनजर लिया गया।

आयोग के अनुसार दिल्ली का एक्यूआई 31 अक्टूबर को 117 दर्ज किया गया था, जो मध्यम श्रेणी में आता है। इसके बाद एक नवंबर को यह बढ़कर 261 पहुंच गया और दो नवंबर को इसमें और वृद्धि होकर 324 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और आईआईटीएम के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बने रहने की आशंका है।

पुणे में आज 21,800 करोड़ की मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पुणे में करीब 21,800 करोड़ रुपये की मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को बताया कि मोदी दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुणे मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन करेंगे और मेट्रो के दूसरे चरण की चार नयी लाइनों की आधारशिला रखेंगे। इस मौके पर वह सभा को भी संबोधित करेंगे।प्रधानमंत्री 8,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनी पुणे मेट्रो की लाइन-तीन यानी पिंक लाइन का उद्घाटन करेंगे।

करीब 23 किलोमीटर लंबी यह लाइन मान से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेट्रो स्टेशन तक जायेगी। इससे हिंजेवाड़ी आईटी हब और शिवाजीनगर के बीच मेट्रो सेवा शुरू होगी। इससे आईटी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों सहित हजारों यात्रियों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी। यह लाइन मौजूदा मेट्रो नेटवर्क से भी जुड़ेगी। इस लाइन की खास बात यह है कि इसका संचालन पूरी तरह महिला ट्रेन ऑपरेटर करेंगी। इसे महिला सशक्तिकरण और सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में खास पहल बताया गया है। इसके अलावा, लाइन की करीब 30 प्रतिशत बिजली की जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी करने की योजना है।

प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के दूसरे चरण की भी आधारशिला रखेंगे। इस पर करीब 13,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें लाइन 2ए, 2बी, 4 और 4ए शामिल हैं। इन नई लाइनों से शहर के प्रमुख आवासीय, व्यावसायिक और आईटी क्षेत्रों तक मेट्रो की पहुंच बढ़ेगी।दूसरे चरण में लाइन 2ए वनाज से चांदनी चौक तक और लाइन 2बी रामवाड़ी से विठ्ठलवाड़ी तक जायेगी। इन दोनों लाइनों की कुल लंबाई करीब 12.75 किलोमीटर होगी।

जापोरिजिया में रूस का हमला, 18 लोगों की मौत

कीव,एजेंसी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन के जापोरिजिया के कोमिशुवाखा गांव में रूस ने मानवीय सहायता केंद्र पर भीषण बमबारी की। इस हमले में एक स्कूल को निशाना बनाया गया जहां लोगों को मदद बांटी जा रही थी। हमले में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पांच घायल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्टई पर हमले की जानकारी साझा की। जेलेंस्की ने पोस्टप में लिखा, रूस ने जापोरिजिया ओब्लास्ट के कोमिशुवाखा गांव पर बेहद भयानक हमला किया। सुबह से ही गांव पर कई हवाई हमले किए गए थे। बम उस स्कूल पर गिराए गए, जिसका इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए किया जा रहा था।

राहुल ने रैली में उमड़े जनसैलाब का जताया आभार

नई दिल्ली, एजेंसी।



कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली में बड़ी संख्या में शामिल होकर वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोगों का आभार जताते हुए कहा है कि इस जनसमर्थन से स्पष्ट हो गया है कि लोकतंत्र और सत्य की जीत होगी तथा आने वाली चुनावों में इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित होगी।

गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा, वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए रिकॉर्ड संख्या में पहुंचने के लिए धन्यवाद। उन्होंने विश्वास जताया कि लोकतंत्र की जीत होगी, सत्य की जीत होगी और इंडिया गठबंधन विजयी होगा।इस बीच संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन की महारैली को बदनाम करने और लोगों को दिल्ली आने से रोकने के लिए व्यापारियों के नुकसान तथा बाजार बंद होने का डर फैलाया गया लेकिन भाजपा का यह पूरा दुष्प्रचार पंक्चर हो गया।

उन्होंने कहा कि इसका मकसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए वोट चोरी और चुनाव आयोग की जवाबदेही के असली मुद्दे से देश का ध्यान भटकाना तथा लोगों को महारैली में शामिल होने से हतोत्साहित करना था लेकिन इसका उलटा असर हुआ।

नौसेना के लिए 53,866 करोड़ रुपये में बनेंगे 8 नए युद्धपोत

नई दिल्ली, एजेंसी।



रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के आठ कार्वेट बनाने के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस ई) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल) के साथ 53,866.50 करोड़ रुपये के अनुबंध किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को यहां बताया कि कर्तव्य भवन-2 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में इन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे स्वदेशी जहाज निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत अच्छी खबर बताते हुए कहा है कि यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। अनुबंध के तहत जी आर एस ई पांच युद्धपोतों का निर्माण करेगा, जबकि जी एस एल को तीन युद्धपोत बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस परियोजना की खास बात यह है कि पहली बार भारतीय नौसेना खुद इन युद्धपोतों का डिजाइन तैयार करेगी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए चुने गए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इनका निर्माण करेंगे।

इन नए युद्धपोतों में आधुनिक मिसाइलों, हथियारों और सेंसर प्रणालियों सहित अत्याधुनिक क्षमताएं होंगी। इनकी मदद से नौसेना हवा, समुद्र की सतह और समुद्र के नीचे के क्षेत्रों में अभियान चला सकेगी।

राहुल गांधी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतराः सुधांशु

भुवनेश्वर,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवारको राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और चुनाव आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी संस्थाओं के प्रति संदेह पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि कांग्रेस और कुछ बाहरी ताकतें भारत की प्रगति तथा 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के विरोध में हैं। त्रिवेदी ने दावा किया कि 12 वर्षों में अत्यधिक गरीबी 27.1 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने कांग्रेस पर ईवीएम, चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय पर सवाल उठाकर अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया।

शाह ने राहुल की दिल्ली रैली को 'घुसपैठियों को बचाओ' रैली बताया

हैदराबाद, एजेंसी।



केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) का दृढ़ता से बचाव किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह मतदाताओं के नाम हटाये जाने के कथित मामले को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।शाह ने यहां 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' महा पदयात्रा में हिस्सा लेने के बाद, मुअज्जम जाही मार्केट में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने कथित वोट बैंक को बचाने के लिए एसआईआर और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (एनआरसी) का विरोध कर रही है।

दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडिया' गठबंधन द्वारा आयोजित 'वोट बचाओ' रैली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह वोट बचाने का अभियान नहीं बल्कि घुसपैठियों को बचाने की कोशिश है।गांधी के 13 करोड़ वोट हटाने के आरोप को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों में वे मतदाता शामिल हैं जिन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया है, जो लोग गुजर चुके हैं, जिनकी प्रविष्टियां दो बार हो गयी हैं, और ऐसे नाम भी शामिल हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है।

उन्होंने मतदाता सूची से ऐसी प्रविष्टियों को हटाने के कांग्रेस के विरोध पर सवाल उठाया और जोर देकर कहा कि केवल भारतीय नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खराब थीं, तो कांग्रेस ने उन राज्यों में अपनी चुनावी जीत को कैसे स्वीकार कर लिया, जहां उसने सरकारें बनायी थीं? उन्होंने कांग्रेस नेता को संसद में उन मुद्दों पर चर्चा में शामिल होने की चुनौती भी दी, जिन्हें विपक्ष उठा रहा है।

तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए शाह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने राज्य को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए एक 'एटीएम' में बदल दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर 'आरआर टैक्स' वसूलने का आरोप लगाया और कहा कि यह पैसा कांग्रेस नेतृत्व तक पहुँचाया जा रहा था। कांग्रेस के छह वादों (गारंटियों) को लागू करने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी द्वारा दिये गये आश्वासनों में से एक भी पूरा नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता सरकार की कथित विफलताओं और भ्रष्टाचार के लिए उसे माफ नहीं करेगी।शाह ने नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें अनुच्छेद 370 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण, तीन तलाक का खात्मा और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज, 16 करोड़ परिवारों को नल से पानी का कनेक्शन और पीएम-किसान योजना के तहत 13 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी है।

सार समाचार

आप के तीन विधायक भाजपा में शामिल हुए

नई दिल्ली, एजेंसी। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के तीन विधायकों के सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने से राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पंजाब कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन मुद्दों के सहारे भाजपा राज्य में अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी एक प्रमुख दावेदार बनी हुई है।

इससे पहले आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसद भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब तीन विधायकों के भी भाजपा में जाने से राज्य में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की भाजपा की कोशिशों को बल मिल सकता है। हरमीत सिंह पठानमाजरा, चेतन सिंह जौरामाजरा और पूर्व आईपीएस अधिकारी से राजनेता बने कुंवर विजय प्रताप सिंह जैसे नेताओं के भाजपा में जाने को मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के लिए प्रतीकात्मक झटका माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब राजनीतिक संदेशों और धारणा की अहम भूमिका होती है।

इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत

मुंबई, एजेंसी। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत में रहने और उनके ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) की ओर से जारी 'लीव इंडिया' नोटिस पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक जारी रखने का फैसला किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। हालांकि, अदालत ने अभिनेता को कथित तौर पर ओसीआई नियमों के उल्लंघन के लिए बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने कहा कि केवल भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देना पर्याप्त नहीं होगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान खान के ओसीआई कार्ड और विरोध प्रदर्शन में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि इमरान खान प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए थे? क्या वह किसी फिल्म की रिलीज या प्रमोशन के लिए वहां गए थे? जज ने कहा कि ओसीआई कार्ड धारकों को भारतीय नागरिकों जैसे सभी अधिकार नहीं मिलते और उन्हें नियमों का पालन करना जरूरी है। अदालत ने यह भी सवाल किया कि इमरान खान पिछले 42 साल से भारत में रह रहे हैं, यहां पढ़ाई की है, काम किया है।

जिलेभर से पहुंचे पत्रकारों ने दी शुभकामनाएं, जनहित और जनसरोकार की पत्रकारिता को मजबूत करने का लिया संकल्प

साहस समाचार टीवी एवं दैनिक साहस समाचार के जिला कार्यालय का भव्य शुभारंभ

शशिकांत गोयल

भिंड, साहस समाचार। सच को सामने लाने और आम जनता की आवाज को बुलंद करने के संकल्प के साथ सोमवार को शहर के भारौली तिराहे के पास दर्पण कॉलोनी, बायपास रोड पर साहस समाचार टीवी एवं दैनिक साहस समाचार के जिला कार्यालय का विधि-विधान एवं पूजा-अर्चना के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे वरिष्ठ पत्रकारों, जिला ब्यूरो चीफ, जिला रिपोर्टरों और संवाददाताओं ने सहभागिता कर संस्थान की नई पहल का स्वागत किया।

कार्यालय का विधिवत उद्घाटन श्रमजीवी पत्रकार संगठन के वरिष्ठ पत्रकार एवं पत्रकारिता जगत में विशिष्ट पहचान रखने वाले राकेश शर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सच दिखाने का साहस ही पत्रकारिता की असली पहचान है। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल खबरें प्रकाशित करना या प्रसारित करना नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर जनसमस्याओं को सामने लाना और आम आदमी की आवाज को जिम्मेदार व्यवस्था तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि संस्थान निष्पक्षता, निर्भीकता और विश्वसनीयता को अपनी प्राथमिकता बनाकर जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देगा। पत्रकार राहुल चौहान ने कहा कि साहस समाचार महज एक समाचार संस्थान नहीं, बल्कि सच को सामने लाने, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने और आम जनता की समस्याओं को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा। जिला स्तर पर कार्यालय की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों और शहरी इलाकों के नागरिकों को अपनी समस्याएं सामने रखने के लिए प्रभावी मंच मिलेगा।



पत्रकार दीपक चौधरी ने कहा कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य घटनाओं की जानकारी देने के साथ उनके पीछे छिपे तथ्यों की पड़ताल करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में सत्ता, प्रशासन और व्यवस्था से जुड़े जनहित के प्रत्येक मुद्दे को निष्पक्षता एवं तथ्यपरकता के साथ उठाना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि साहस समाचार जनता से जुड़े उन मुद्दों को भी प्रमुखता देगा, जो अक्सर जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचने के बावजूद अनदेखे रह जाते हैं।

साहस समाचार टीवी एवं दैनिक साहस समाचार परिवार की ओर से आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, जागरूक युवाओं और पत्रकार साथियों से अपील की गई कि वे अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाओं और जनसमस्याओं की जानकारी संस्थान तक पहुंचाएं। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक लापरवाही, अपराध और विकास कार्यों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

संस्थान की ओर से स्पष्ट किया गया कि प्राप्त समाचारों की तथ्यों के आधार पर पड़ताल की जाएगी। संबंधित पक्षों का पक्ष जानने और आवश्यक पुष्टि के बाद ही खबरों को प्रकाशित एवं प्रसारित करने का प्रयास किया जाएगा। दैनिक साहस समाचार के माध्यम से प्रिंट मीडिया तथा साहस समाचार टीवी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में जनहित के मुद्दों को व्यापक स्तर पर पहुंचाया जाएगा।

संस्थान का मानना है कि सार्थक पत्रकारिता वही है, जो समाज के प्रत्येक वर्ग की आवाज बने। गरीब, मजदूर, किसान, पीड़ित, वंचित और आम नागरिकों की समस्याओं को प्रमुखता देना ही पत्रकारिता के मूल दायित्वों में शामिल है।

समारोह में पहुंचे वरिष्ठ पत्रकारों एवं पत्रकार साथियों ने अपने अनुभव और विचार साझा करते हुए संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि किसी भी समाचार संस्थान की वास्तविक पहचान उसके कार्यालय और संसाधनों से नहीं, बल्कि उसकी निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता से बनती है। नई शुरुआत के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, इसलिए पत्रकारिता के स्थापित मूल्यों को सर्वोपरि रखना आवश्यक है। इस अवसर पर साहस समाचार परिवार की ओर से जिलेभर से पहुंचे सभी वरिष्ठ पत्रकारों, जिला ब्यूरो चीफ, जिला रिपोर्टरों, संवाददाताओं और पत्रकार मित्रों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

अंत में संस्थान परिवार ने संकल्प लिया कि साहस समाचार टीवी एवं दैनिक साहस समाचार जनता के विश्वास पर खरा उतरने, सच्चाई को सामने लाने, जनसमस्याओं की पड़ताल करने और निष्पक्ष पत्रकारिता के मूल्यों को कायम रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। साहस समाचार टीवी एवं दैनिक साहस समाचार का संकल्प—खबर वही, जो जनता के सरोकार से जुड़ी हो; पत्रकारिता वही, जिसमें सच दिखाने का साहस हो।

दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की रैली से विपक्ष होगा मजबूतः राकेश टिकैत

टिकैत ने कहा कि दिल्ली में आयोजित विपक्ष की रैली से विपक्षी दलों को मजबूती मिलेगी।

गाजियाबाद,एजेंसी।



भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सोमवार को गाजियाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में आयोजित इंडिया ब्लॉक की महारैली, जेन-जी के विरोध प्रदर्शनों, किसानों की चुनावी रणनीति और राजधानी में प्रदूषण को लेकर लागू किए जा रहे नियमों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

टिकैत ने कहा कि दिल्ली में आयोजित विपक्ष की रैली से विपक्षी दलों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि रैली में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। राहुल गांधी के नेतृत्व में आयोजित रैली का उल्लेख करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि वर्ष 2020 के दिल्ली किसान आंदोलन के बाद विपक्ष की यह पहली बड़ी रैली थी।

उन्होंने कहा कि अब तक किसान अपने स्तर पर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों ने पहली बार इस तरह का बड़ा आयोजन किया है। विपक्ष को प्रदेश स्तर पर भी इसी तरह बड़ी रैलियां आयोजित करनी चाहिए, जिससे उसकी एकजुटता और ताकत बढ़ सके। जेन-जी के विरोध प्रदर्शनों और वर्ष 2027 तथा 2029 के चुनावों में युवाओं की भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर टिकैत ने कहा कि युवा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, उनका आंदोलन अच्छा है।

उन्होंने कहा कि युवा और बच्चे आगे आ रहे हैं तथा देश का युवा वर्ग भी उनके साथ जुड़ रहा है। किसानों की चुनावी रणनीति को लेकर राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया कि भारतीय किसान यूनियन किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव में समर्थन नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में सभी लोगों को एकजुट होकर साथ रहना चाहिए, लेकिन चुनाव में किसे मतदान करना है, यह प्रत्येक व्यक्ति का अपना निर्णय है। आंदोलन में शामिल होने वाले लोग सत्ता पक्ष को भी मतदान करते हैं। इसलिए आंदोलन और चुनाव को अलग-अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए।

दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर 10 साल पुरानी गाड़ियों के प्रवेश पर लगाए जा रहे प्रतिबंध को लेकर टिकैत ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आधार उनकी उम्र नहीं, बल्कि उनकी फिटनेस होनी चाहिए। वाहनों की स्थिति और उनके वास्तविक इस्तेमाल को ध्यान में रखकर नियम बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक वाहनों और घरों में खड़ी रहने वाली निजी गाड़ियों के इस्तेमाल में काफी अंतर होता है। इसके बावजूद सभी वाहनों पर एक समान नियम लागू करना उचित नहीं है। टिकैत ने इस नीति का वैचारिक रूप से विरोध करने की बात कही। पराली जलाने से दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के सवाल पर राकेश टिकैत ने किसानों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि किसानों पर प्रदूषण फैलाने के गलत आरोप लगाए जाते हैं। उनके अनुसार, अब किसान खेतों में पराली जलाने के बजाय उसे खेतों से उठाकर दूसरी जगह उपयोग के लिए भेज रहे हैं। पराली का इस्तेमाल अन्य कार्यों में किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने अपने बयान में विपक्षी एकजुटता, युवाओं की भागीदारी और किसानों से जुड़े मुद्दों पर विचार रखे।

अधिकारियों को मतदाता सूचियों की दोबारा जांचने निर्देश

-फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के आवेदनों का शीघ्र निपटान करने के निर्देश

गुरुग्राम,एजेंसी।



जिले में सोमवार को डीसी उत्तम सिंह ने फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की। इसमें अधिकारियों को मतदाता सूची की दोबारा जांच करने निर्देश दिए गए। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार नोटिस चरण तथा दावे एवं आपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया 20 नवंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को किया जाएगा।

डीसी ने कहा कि पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई मतदाता सूचियों का बारीकी से सत्यापन किया जाए और क्रॉस चेकिंग के माध्यम से किसी भी संभावित त्रुटि को दूर किया जाए। साथ ही, मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम शामिल करने तथा मतदाताओं के विवरण को सही रखने के लिए सभी संबंधित अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारी पूरी गंभीरता से कार्य करें तथा पुनरीक्षण से जुड़े प्रत्येक चरण की जांच सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे।

डीसी ने बताया कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को एसआईआर के दौरान प्राप्त फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के आवेदनों का भी नियमानुसार शीघ्र निपटान करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने से संबंधित दावों के लिए फॉर्म-7 तथा मतदाता सूची में दर्ज विवरण में संशोधन सहित अन्य निर्धारित सेवाओं के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाता है। इन आवेदनों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करते हुए समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर बादशाहपुर एसडीएम संजीव सिंगला, पटौदी एसडीएम दिनेश लुहाच, गुरुग्राम एसडीएम हितेंद्र कुमार, सोहना एसडीएम अखिलेश यादव, सीटीएम ज्योति नागपाल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

महिला पहलवानों से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप

गाजियाबाद,एजेंसी।



जनपद में महिला पहलवानों के साथ कथित छेड़छाड़, अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि डगरपुर में आयोजित कुश्ती दंगल में भाग लेने जा रही महिला पहलवानों को रास्ते में रोककर उनके साथ अभद्रता की गई और विरोध करने पर मारपीट की गई। शिकायत में एशिया स्तर की कुश्ती खिलाड़ी के साथ भी घटना होने की बात कही गई है।

इसके अलावा एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ गलत हरकत करने का गंभीर आरोप भी लगाया गया है। प्राप्त एफआईआर की प्रति के अनुसार, शिकायतकर्ता दीपक शर्मा ने थाना नंदग्राम में दी शिकायत में बताया कि 1 नवंबर 2026 को सुबह करीब 11:30 बजे वह महिला पहलवानों और एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ अपने वाहन से डगरपुर में आयोजित कुश्ती दंगल में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान मोटी रोड पर कुछ लोगों ने उनका वाहन रुकवा लिया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वाहन में सवार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की गई। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में शिकायतकर्ता और महिला पहलवानों को चोटें आने की बात भी कही गई है। साथ ही आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

मामले में एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ शारीरिक शोषण का प्रयास किए जाने की भी गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

शिकायतकर्ता दीपक शर्मा ने नितिन त्यागी, अर्जुन त्यागी और कपिल त्यागी को मुख्य आरोपी बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में घटना से संबंधित वीडियो साक्ष्य होने का भी उल्लेख किया गया है।

इस घटना से महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है।

बैनामा लेखक की पड़ोसी वकील को फंसाने की साजिश का खुलासा, तीन गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा,एजेंसी।



एजेंसी।पुलिस ने बैनामा लेखक पर हुई फायरिंग मामले का सोमवार को पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साजिशकर्ता, उसका भाई और एक साथी अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक बैनामा लेखक हरेंद्र नागर ने अपने हिस्ट्रीशीटर भाई के साथ मिलकर अपने पड़ोसी विकल विकास सैन को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग कराई थी।

ग्रेटर नोएडा के डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि दादरी कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार दो युवकों ने 25 अक्तूबर को बैनामा लेखक हरेंद्र नागर के ऊपर फायरिंग की थी। बैनामा लेखक ने इस मामले में अपने पड़ोसी वकील विकास सेन को आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली।

पुलिस की जांच में सामने आया की घटना के समय आरोपी विकास अपने घर पर था। पुलिस की जांच में सामने आया कि वादी हरेंद्र नागर ने अपने हिस्ट्रीशीटर भाई सत्ते, भतीजे प्रतीक उर्फ कलुआ, साले अतुल भाटी और बेटे अभिषेक नागर समेत अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। इसके तहत अतुल भाटी और कलुआ उर्फ प्रतीक को घर बुलाकर कैमरे के सामने खुद पर फायरिंग कराई। इसके बाद पड़ोसी विकास सैन के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने इस मनगढ़ंत घटना का खुलासा कर सोमवार को बिसाहड़ा अंडरपास से तीन वांछित आरोपी प्रतीक उर्फ कलुआ, अतुल भाटी और अभिषेक नागर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, एक बाइक और सीसीटीवी की डीवीआर बरामद की। पुलिस साजिशकर्ता वादी हरेंद्र, उसके भाई सत्ते और आकाश चपराना की तलाश में जुटी है।

डीसीपी ने बताया कि वादी हरेंद्र और उसका भाई सतेंद्र उर्फ सत्ते को दादरी में वर्ष 2007 में हुई एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। दोनों भाई पैरोल पर जेल से छूटकर बाहर आए हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर पड़ोसी को फंसाने के लिए साजिश रची। डीसीपी के मुताबिक बताया जा रहा है कि खुद के ऊपर फायरिंग करने का मकसद असलाह का लाइसेंस बनवाना और सुरक्षा गनर लेना था। हालांकि, पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। मुख्य आरोपी हरेंद्र और उसके भाई सत्ते के पकड़े जाने के बाद घटना का सही मकसद पता चल सकेगा।

मच्छरमुक्त बनाने के लिए मेयर ने संभाली कमान

गुरुग्राम,एजेंसी।

साइबर सिटी को स्वच्छ, स्वस्थ और मच्छरमुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने शहरभर में व्यापक स्तर पर फॉगिंग अभियान शुरू कर दिया है। महापौर राजरानी मल्होत्रा के कड़े निर्देशों के तहत मच्छरों की रोकथाम और नागरिकों को मच्छरजनित बीमारियों से बचाने के लिए विभिन्न कॉलोनियों और रिहायशी क्षेत्रों में नियमित रूप से फॉगिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वच्छता और व्यवस्था का जायजा लेने के लिए महापौर राजरानी मल्होत्रा स्वयं प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों का औचक दौरा कर रही हैं। इन दौरों के दौरान वे क्षेत्र में साफ-सफाई, कचरा उठान और अन्य नागरिक सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण कर रही हैं।

कार का शीशा तोड़कर नकदी और लैपटॉप चुराए

ग्रेटर नोएडा,एजेंसी।

कासना कस्बे में बदमाशों ने निजी अस्पताल के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़कर दो लैपटॉप और 55 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। पीड़ित अस्पताल में भर्ती अपने किसी परिचित को देखने गए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कासना कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एल्डिको मिडोज सोसाइटी निवासी नरेंद्र सिंह के परिचित कासना कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं।

वह 31 अक्तूबर को उन्हें देखने अस्पताल गए थे। उन्होंने अपनी कार अस्पताल के बाहर सड़क किनारे खड़ी की थी। वह अपने परिचित से मिलकर बाहर आए तो कार का शीशा टूटा मिला। कार में रखा बैग गायब था, जिसमें 55 हजार रुपये और दो लैपटॉप थे। उन्होंने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की।

फरीदाबाद पुलिस का 12वां वीकेंड अभियान, तीन दिन में 116 गिरफ्तार

फरीदाबाद,एजेंसी।

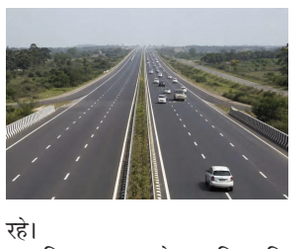
फरीदाबाद पुलिस द्वारा अपराधियों पर शिकंजा कसने और जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए विशेष वीकेंड अभियान चलाया हुआ है। पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता के निर्देशन में 30 अक्टूबर से एक नवंबर तक चलाए गए तीन दिवसीय इस अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न मामलों में 116 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 22.720 किलोग्राम गांजा, चार देसी कट्टा, एक कारतूस, 183 बोतल देसी शराब, व जुआ अधिनियम के अंतर्गत एक लाख 47 हजार 450/- रुपए बरामद किये हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अभियान के तहत जिले के विभिन्न थानों, अपराध शाखाओं और विशेष टीमों ने कार्रवाई करते हुए अपराधियों, नशा तस्करों, अवैध शराब बेचने वालों तथा जुआ खेलने और खिलाने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा ही है। साथ ही 22 गुमशुदा व्यक्तियों को भी तलाश कर परिजनों से मिलाया है। विशेष अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए 22.720 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, वहीं 183 बोतल देसी शराब, 5 बोतल अंग्रेजी शराब भी बरामद की है।

उन्होंने आगे बताया कि फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखाओं की टीम ने अवैध हथियारों पर कार्रवाई करते अभियान के दौरान 4 देसी कट्टा व एक कारतूस बरामद किया है। इसी प्रकार जुआ खेलने वालों पर कार्रवाई करते हुए 11 लोगों गिरफ्तार कर एक लाख 47 हजार 450/- रुपए बरामद किये हैं। उन्होंने और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के दौरान उद्घोषित अपराधियों और जमानत पर फरार आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से कानून से बचकर घूम रहे 27 आरोपितों पर शिकंजा कसने में मदद मिली।

एक्सप्रेस-वे को स्वच्छ बनाने के लिए एनएचएआई कार्रवाई करेः निगम आयुक्त

गुरुग्राम,एजेंसी।



गुरुग्राम में वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने सभी संबंधित विभागों को अपने अधिकार क्षेत्र की सड़कों का नियमित रखरखाव करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों को दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस-वे को दुरुस्त करने और वहां सफाई, हरियाली और रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा है।

सोमवार को नगर निगम कार्यालय में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निगम आयुक्त ने यह निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम गुरुग्राम, (जीएमडीए), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम और यातायात पुलिस सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस-वे या उसके आसपास निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की अवैध डंपिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एनएचएआई इसके खिलाफ प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करे। यदि कोई व्यक्ति या एजेंसी एक्सप्रेस-वे के पास सीएंडडी वेस्ट डालती पाई जाती है, तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे की स्वच्छता व हरियाली बनाए रखना एनएचएआई की मुख्य जिम्मेदारी है।निगम आयुक्त ने तमाम विभागों को निर्देश दिए कि वह अपने अधीन आने वाली सड़कों का निरीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर उनकी स्थिति सुधारें। एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों को उद्योग विहार क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करने को कहा गया है।

उन्होंने आदेश दिए कि सड़कों को धूल-मिट्टी, सीएंडडी वेस्ट और कचरे से पूरी तरह मुक्त रखने के लिए नियमित सफाई की जाए, क्योंकि सड़कों पर जमी धूल प्रदूषण बढ़ाने का मुख्य कारण बनती है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़कों को एंड-टू-एंड पेव्ड कराने पर जोर दिया गया ताकि किनारों पर मिट्टी जमा न हो। इसके अलावा यातायात पुलिस को सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने, ग्रीन बेल्ट को व्यवस्थित करने तथा पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथों की मरम्मत के भी निर्देश दिए गए।

निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के तहत निर्धारित सिटी एक्शन प्लान के लक्ष्यों को तय समयसीमा में पूरा किया जाना चाहिए।

किन्नर बनकर उगाही करने वाली महिलाएं पकड़ीं, दो हुई फरार

फरीदाबाद,एजेंसी।

शहर के नेहरू ग्राउंड में किन्नर बनकर उगाही करने वाली महिलाओं की गैंग को असली किन्नरों ने पकड़ लिया। इस दौरान दो महिलाएं भागने में कामयाब रहीं, जबकि दो को असली किन्नरों ने पकड़ लिया और थाना कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल दोनों थाने में बैठी थीं और इस बाबत किन्नरों की गुरु मनीषा चौहान ने पुलिस में शिकायत दी।

मनीषा चौहान ने बताया कि सोमवार को उन्हें सूचना मिली कि नेहरू ग्राउंड में कुछ नकली किन्नर दुकानदारों से जबरन उगाही कर रहे हैं और पैसे न देने पर उन्हें गालियां दे रहे हैं। सूचना मिलने पर मनीषा चौहान ने कुछ किन्नरों को मौके पर भेजा तो उन्होंने देखा कि चार किन्नर एक वैन में बैठी हुईं थीं, जब उन्होंने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि वह महिलाएं है, जो कि किन्नर बनकर लोगों से पैसा उगाह रही थी।

इस बीच मौका देखकर दो महिलाएं फरार हो गयीं ,जबकि दो महिलाओं को किन्नरों व स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। किन्नर गुरु मनीषा चौहान ने बताया कि वह टाउन में साल में एक बार यानी दिवाली पर जाते है, जहां लोगों को दुआएं देकर उनकी इच्छा अनुसार दक्षिणा लेती है, लेकिन अगर ऐसे ही नकली किन्नर उनके काम धंधे को प्रभावित करेंगे तो उनके समक्ष भारी परेशानियां हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि इससे पूर्व कुछ युवकों को भी किन्नर बने हुए पकड़ा गया था, जो बाद में भाग गए थे। बताया जाता है कि यह महिलाएं दिल्ली की रहने वाली है।

चार एंबुलेंस पर 50 लाख का डीजल खर्च, जांच कमेटी हुई गठित

फरीदाबाद,एजेंसी।



फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल में महीनों से खड़ी चार एंबुलेंस के नाम पर करीब 50 लाख रुपए का डीजल खरीदे जाने का मामला सामने आया है। मामला उजागर होने के बाद सिविल सर्जन डॉ. जयंत आहूजा ने जांच कमेटी गठित की। कमेटी को 15 दिन के अंदर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। सीएमओ ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनएचएम डायरेक्टर वीरेंद्र यादव भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं।

सोमवार को बीके अस्पताल के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, हाल में ही पंचकूला स्थित मुख्यालय ने एम्बुलेंस में फ्यूल कार्ड के जरिए होने वाले लेनदेन की जांच की थी। इस दौरान सामने आया कि कुछ एम्बुलेंस बिना चले ही उनके नाम पर पेट्रोल पंप से डीजल खरीदा जा रहा था।

यह सिलसिला एक-दो बार नहीं, बल्कि लगातार जारी था। जांच में करीब 50 लाख रुपए का ईंधन खरीदे जाने का अंदेशा जताया गया है। खास बात यह है कि जिस अवधि में इन एंबुलेंस के नाम पर डीजल खरीदा गया, उस दौरान वे अपनी निर्धारित जगह से कहीं नहीं गई थीं। विभाग के मुताबिक, एचआर 38जीवी 3491 और एचआर-38 जीवी 9863 नंबर की दो एम्बुलेंस तीन से चार महीने से अस्पताल की मोर्चरी के पास खड़ी थीं। इसके बावजूद 11 अक्टूबर तक इनके फ्यूल कार्ड से डीजल भरवाने की एंट्रियां दर्ज मिलीं। वहीं एचआर38जेड0951 और एचआर38जीवी1670 नंबर की अन्य दो एंबुलेंस जनवरी और अगस्त से एजेंसी की वर्कशॉप में खड़ी थीं। इनके फ्यूल कार्ड से भी 16 सितंबर और 11 अक्टूबर तक डीजल भरवाने का रिकॉर्ड मिला। डिप्टी सिविल सर्जन (एनएचएम) विनय गुप्ता ने 16 अक्टूबर को आरटीएस फ्लीट मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में डीजल भरवाने का पूरा ब्योरा, लेनदेन की जानकारी और जिम्मेदार कर्मचारियों के नाम मांगे गए।

प्रत्येक एम्बुलेंस के हिसाब से डीजल भरवाने की तारीख, मात्रा, कीमत, पेट्रोल पंप और संबंधित कर्मचारियों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए। बीके अस्पताल के सीएमओ डॉ. जयंत आहूजा ने 20 अक्टूबर को मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की। कमेटी को 15 दिन के अंदर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

सीएमओ के मुताबिक, रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एम्बुलेंस महीनों से एक ही जगह खड़ी थीं, तो उनके नाम पर डीजल किसकी अनुमति से खरीदा गया।

मूर्धन्य पत्रकार प्रभाष जोशी की पुण्यतिथि मनाई गई

गाजियाबाद, साहस समाचार।



सुप्रसिद्ध पत्रकार प्रभाष जोशी जी की सत्रहवीं पुण्यस्मृति के अवसर पर मेवाड़ संस्थान गाजियाबाद में रविवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पंडित हरिदत्त शर्मा एवं शिष्यों द्वारा मधुर भक्ति संगीत एवं गायन प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा कबीर भजन एवं अन्य भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। राम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो तथा शिव कैलाशो के वासी जैसे मंत्रमुग्ध कर देने वाले भक्ति गीतों ने दर्शकों का मन मोह लिया कार्यक्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष रायबहादुर राय, मेवाड़ संस्थान के अध्यक्ष डॉ अशोक कुमार गदिया, मेवाड़ संस्थान की निदेशक डॉ अलका अग्रवाल, टीवी 9 भारतवर्ष के निदेशक हेमंत शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ ए एस देव,प्रभाष जोशी की पत्नी उषा जोशी, प्रभाष परंपरा न्यास के न्यासी नरेश सिरोही, वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ शुक्ल, मनोज मिश्र, अखिलेश शर्मा समेत बड़ी संख्या में पत्रकार और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद थे।

RNI.No DLHIN/25/A2841 स्वामी, प्रकाशक, संपादक देवेंद्र सिंह तोमर एवं मुद्रक रवि भारद्वाज मै. मारुती नंदन प्रिंटर्स एवं पब्लिशर, शक्ति कॉम्प्लेक्स 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110042 से मुद्रित एवं हॉउस नंबर 16/ 9980, गली नंबर-5, सराय रोहिल्ला न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित।

संपादकीय कार्यालय - B4/265B केशव पुरम नई दिल्ली -110005। फोन-011-40106508 मोबाइल-9911466900/ 8076353913। Email.saahassamachardainik@gmail.com

संपादक देवेंद्र सिंह तोमर

इस अंक में प्रकाशित खबरों एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा नई दिल्ली के न्यायालय में होगा।

दिल्ली में पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन

दो पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर सोमवार को पुलिस विभाग में असंतोष सामने आया।

नई दिल्ली,साहस समाचार।



दिल्ली के शाहदरा थाने में पुलिसकर्मियों और अधिवक्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद दो पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर सोमवार को पुलिस विभाग में असंतोष सामने आया। तबादले के विरोध में करीब 100 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर एकत्र हुए और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल रहीं।

प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने तीन प्रमुख मांगें रखते हुए आरोपी अधिवक्ता की गिरफ्तारी, थाने में अधिवक्ताओं के प्रवेश को नियंत्रित करने और कचहरी जाने वाले पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों की पहली मांग है कि पुलिसकर्मियों के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार करने और उन्हें धमकी देने वाले अधिवक्ता को गिरफ्तार किया जाए।

उनका कहना है कि पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दूसरी मांग के तहत पुलिसकर्मियों ने कहा कि किसी भी थाने में थाना प्रभारी के कक्ष में एक समय पर 5 से अधिक अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि इससे थाने के भीतर अनावश्यक भीड़ और विवाद की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। तीसरी मांग कचहरी जाने वाले पुलिसकर्मियों की सुरक्षा से संबंधित है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि न्यायालय परिसर में ड्यूटी अथवा अन्य कार्यों से जाने वाले पुलिसकर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार जैसी घटनाओं को रोका जा सके।

प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों ने सहायक पुलिस आयुक्त मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार को उनकी पूर्व तैनाती पर वापस भेजने की मांग भी उठाई। पुलिसकर्मियों का कहना है कि विवाद के बाद दोनों अधिकारियों का तबादला किया जाना उचित नहीं है और उनकी बहाली पर विचार किया जाना चाहिए।

प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने और विभाग के भीतर संवाद की व्यवस्था मजबूत करने की अपील की। दरअसल, पूरे विवाद की शुरुआत 23 अक्तूबर को शाहदरा थाने के भीतर पुलिस अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच हुई झड़प से हुई थी।

इस घटना में अधिवक्ता ललित बंसल के सिर में गंभीर चोट आई थी। घटना के बाद पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच तनाव बढ़ गया था। इसके विरोध में जिला अदालत के अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। वकीलों की हड़ताल और विरोध के बीच दिल्ली पुलिस ने 28 अक्तूबर को सहायक पुलिस आयुक्त मनस्वी वशिष्ठ का तबादला गांधी नगर के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी पद से विशेष पुलिस इकाई महिला एवं बाल में कर दिया। वहीं, शाहदरा थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार को भी उनके पद से हटाकर सुरक्षा इकाई में भेज दिया गया। दोनों अधिकारियों के तबादले के बाद अधिवक्ताओं ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी।

एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने प्रदर्शन को स्वाभाविक रूप से सामने आया विरोध बताते हुए कहा कि वह भी इसमें शामिल हो रही हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से पुलिसकर्मियों की समस्याओं और शिकायतों को रखने के लिए उचित मंच उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस संबंध में उन्होंने औपचारिक आवेदन भी दिया।वशिष्ठ ने कहा कि पुलिस थानों के भीतर हो रही अराजकता और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार और अराजकता फैलाते हैं। ऐसे तत्व केवल पुलिस ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए नुकसानदायक हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त के साथ सीधे संवाद आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा।

बात मुद्दे की



आलोक गौड़

जहरीली हवा में सांस लेना अब दिल्ली की मजबूरी क्यों?

नई दिल्ली। दिल्ली में हवा नहीं, जहर बह रहा है। सांस लेना किसी जमाने में जिंदगी की सबसे सहज प्राकृतिक प्रक्रिया हुआ करती थी, लेकिन देश की राजधानी में अब यही काम जोखिम उठाकर करना पड़ रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि सुबह घर से निकलने से पहले लोग मौसम नहीं, हवा की गुणवत्ता का हाल पूछते हैं। बच्चों को बाहर खेलने भेजना है या नहीं, बुजुर्गों को सैर पर जाना चाहिए या नहीं, घर की खिड़कियां खोलनी हैं या बंद रखनी हैं, इन फैसलों के लिए अब डॉक्टर की सलाह से ज्यादा वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों पर भरोसा करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली को इस मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है?

दीवाली अभी आई भी नहीं है और दिल्ली की हवा का दम पहले ही घुटने लगा है। देर रात वायु गुणवत्ता सूचकांक 466 तक पहुंच जाना किसी सामान्य मौसमी उतार-चढ़ाव का संकेत नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की विफलता का प्रमाण है जो हर साल प्रदूषण से निपटने के बड़े-बड़े दावे करती है। एक नवंबर से बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों पर पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया। सवाल है कि जब प्रदूषण के कारणों की पहचान पहले से है तो फिर सरकारें साल के आखिरी महीनों में ही क्यों जागती हैं? क्या प्रदूषण का कैलेंडर केवल अक्टूबर और नवंबर में खुलता है? क्या बाकी आठ-दस महीने दिल्ली की हवा अपने आप साफ रहती है?

दिल्ली में प्रदूषण कोई अचानक आ जाने वाली प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह वर्षों की प्रशासनिक लापरवाही, अधूरी योजनाओं, कमजोर निगरानी और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का नतीजा है। हर साल सर्दियां आते ही वही कहानी दोहराई जाती है। निर्माण कार्यों पर रोक, वाहनों पर प्रतिबंध, पानी का छिड़काव, एंटी स्मॉग गन, स्कूलों को लेकर दिशा-निर्देश और लोगों को घरों में रहने की सलाह। फिर कुछ दिन बाद मौसम बदलता है और सरकारों की चिंता भी हवा हो जाती है। अगले साल फिर वही बैठकें, वही घोषणाएं और वही प्रतिबंध। आखिर इस अंतहीन सिलसिले का अंत कब होगा?

विडंबना देखिए कि दिल्ली में करोड़ों रुपये के एयर प्यूरीफायर लगाए जाने के बावजूद प्रदूषण का स्तर लोगों को राहत नहीं दे पा रहा। आईटीओ जैसे प्रमुख इलाके में एयर प्यूरीफायर लगाने के बाद भी वहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 351 दर्ज होना इस बात का संकेत है कि तकनीकी इंतजामों और प्रचार से हवा की समस्या का समाधान नहीं होने वाला। सवाल केवल मशीनें लगाने का नहीं है, सवाल उस हवा को साफ करने का है जिसमें दिल्ली के करोड़ों लोग सांस लेने को मजबूर हैं। अगर सार्वजनिक स्थानों पर मशीनें लगाने के बाद भी हवा जहरीली है तो सरकार को अपनी रणनीति पर जवाब देना चाहिए।

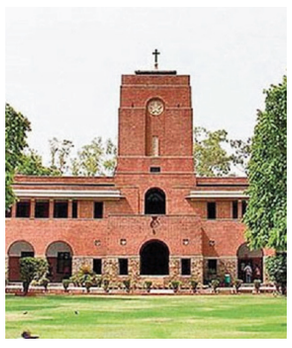
यह भी समझना होगा कि प्रदूषण का बोझ सभी लोग बराबर नहीं उठाते। जिनके पास साधन हैं, वे घरों में एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, कार से सफर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कुछ दिन के लिए दिल्ली से बाहर जा सकते हैं। लेकिन दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी वाले, निर्माण श्रमिक, सफाई कर्मचारी और सड़क किनारे काम करने वाले हजारों लोगों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। उन्हें जहरीली हवा में ही काम करना है और उसी से अपने परिवार का पेट पालना है। क्या सरकार ने कभी सोचा है कि प्रदूषण के खिलाफ उसकी लड़ाई में सबसे ज्यादा कीमत कौन चुका रहा है? जिस मजदूर के पास मास्क खरीदने के पैसे नहीं हैं, उसके लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक का आंकड़ा क्या मायने रखता है?

बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर कहीं अधिक गंभीर है। सांस संबंधी बीमारियां, आंखों में जलन, खांसी, गले में परेशानी और फेफड़ों पर पड़ने वाला दबाव अब दिल्लीवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। अस्पतालों में सांस की तकलीफ लेकर पहुंचने वालों की परेशानी को केवल मौसम का असर कहकर टाला नहीं जा सकता। बच्चों का बचपन घरों के भीतर कैद हो रहा है। खेल के मैदानों में दौड़ने के बजाय उन्हें प्रदूषण से बचने की सलाह दी जा रही है। जिस राजधानी में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के दावे किए जाते हैं, वहां बच्चों को साफ हवा तक उपलब्ध न करा पाना कैसी उपलब्धि है?

प्रदूषण की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने का खेल भी पुराना हो चुका है। दिल्ली सरकार कभी पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराती है, कभी वाहनों को और कभी मौसम को। हरियाणा और पंजाब की सरकारों के अपने तर्क हैं। केंद्र सरकार की अपनी समितियां और बैठकें हैं। लेकिन दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले नागरिकों को इन राजनीतिक बहसों से क्या हासिल हुआ? हवा का कोई राजनीतिक दल नहीं होता और न ही प्रदूषण किसी राज्य की सीमा पर रुकता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच प्रदूषण का साझा संकट है तो उसका समाधान भी साझा होना चाहिए।

आंबेडकर, महिला और आतंकवाद पर लिखी सामग्री पर आपत्ति, डीयू शिक्षक सेवामुक्त

नई दिल्ली,साहस समाचार।



दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई, पूर्व में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग) ने राजनीति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सरिपल्ली वी. रविकिरण को प्रोबेशन अवधि के दौरान तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त कर दिया है। यह कार्रवाई बीए राजनीति विज्ञान के अध्ययन सामग्री से जुड़े मुद्दे पर की गई। विश्वविद्यालय के शासकीय निकाय की सिफारिश पर कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने सेवामुक्ति को मंजूरी दी। 30 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में इसकी जानकारी दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्व-अध्ययन सामग्री में डॉ. बीआर आंबेडकर, महिलाओं और आतंकवाद से संबंधित टिप्पणियों कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। सामग्री में इस्तेमाल किए गए शब्दों और प्रस्तुत किए गए विचारों पर सवाल उठे थे। समीक्षा समिति ने सामग्री में महिलाओं और आंबेडकर के संदर्भ में अपमानजनक, दमनकारी और नकारात्मक भाषा के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद शिक्षक के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू की गई। आंबेडकर और महिलाओं के संदर्भ में इस्तेमाल की गई भाषा को अपमानजनक और नकारात्मक बताया गया था। नारीवाद से संबंधित प्रस्तुति को लेकर भी आपत्ति जताई गई थी। आतंकवाद से जुड़े संदर्भ भी विवाद का हिस्सा बने।

इस पूरे मामले में सेवामुक्त किए गए शिक्षक को फोन कर जब उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया न ही मैसेज का जवाब दिया। शिक्षक के खिलाफ डीयू द्वारा की गई कार्रवाई का कुछ शिक्षक संगठनों ने विरोध जताया है। इसे अलोकतांत्रिक और गलत बताया है। मामले को लेकर एसओएल के शिक्षकों और छात्रों ने कुलपति को संयुक्त प्रतिनिधित्व भेजकर विश्वविद्यालय की छवि पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने ऐसी अध्ययन सामग्री का विरोध किया था, जिसमें उनके अनुसार महिलाओं और डॉ. आंबेडकर के लिए अपमानजनक तथा नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। प्रतिनिधित्व में शिक्षकों और छात्रों ने कहा था कि वे ऐसी सामग्री की कड़ी निंदा करते हैं और इस तरह के विचार व्यक्त करने वालों के खिलाफ एकजुट हैं। इस विरोध ने मामले को विश्वविद्यालय के भीतर भी गंभीर मुद्दा बना दिया था।

जेल में एक ही स्थान पर तीन साल से तैनात कर्मचारियों का होगा तबादला

नई दिल्ली,साहस समाचार।



दिल्ली की तिहाड़ जेल में भ्रष्टाचार को लेकर मिलने वाली शिकायत को लेकर दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली की जेल में एक ही जगह तीन वर्षों से तैनात सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। उन्होंने ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों का सामना कर रहे कुछ अधिकारियों के पिछले दस वर्षों के तैनाती संबंधी विस्तृत रिकॉर्ड भी मांगे हैं।

गृह मंत्री आशीष सूद द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तहत मुख्य प्रवक्ता (सीपीआरओ) को फैक्ट्री, खरीद (प्रोक्योरमेंट) विंग तथा पहली बार अपराध करने वाले कैदियों, आर्थिक अपराधों से जुड़े कैदियों और सिविल बंदियों के लिए निर्धारित जेलों जैसे संवेदनशील विभागों में निर्धारित अवधि से अधिक समय से तैनात अधिकारियों की पूरी सूची प्रस्तुत करने को कहा गया है। जेलों के भीतर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसी आधुनिक स्कैनिंग तकनीक अपनाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। जिसके माध्यम से कैदियों को नुकसान पहुंचाए बिना तंबाकू और मादक पदार्थों की तस्करी का पता लगाया जा सके। दिल्ली सरकार ने जेलों में बंदियों के कल्याण और सुरक्षा को लेकर भी सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि कैदियों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन और दवाइयों की गुणवत्ता तथा उनकी बाजार दरों का सत्यापन किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को रोका जा सके।

हमारा प्रशासन सुधारात्मक संस्थानों के भीतर भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और व्यवस्थागत अक्षमता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों का स्थानांतरण करना निहित स्वार्थों पर अंकुश लगाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दिल्ली की सभी जेलों में पूर्ण ईमानदारी एवं जवाबदेही स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डीयू के सीडीओई ने सहायक प्रोफेसर को किया बर्खास्त

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली विश्वविद्यालय के दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीडीओई) ने राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. सरीपल्ली वी रविकिरण को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इस संबंध में सीडीओई ने 30 अक्तूबर को आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, डॉ रविकिरण की नियुक्ति मई 2023 को हुई थी। 2025 को उनकी प्रोबेशन अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी गई थी।

हालांकि, बढ़ाई गई अवधि के दौरान भी उनके काम और आचरण में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। आदेश में कहा गया है कि केंद्र ने समय-समय पर उन्हें काम में कमियों की जानकारी दी। साथ ही अपना पक्ष रखने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई और लिखित जवाब देने के कई अवसर भी दिए गए।

सीडीओई की गवर्निंग बॉडी ने लगातार असंतोषजनक प्रदर्शन को देखते हुए सेवा से हटाने की सिफारिश की। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी इस सिफारिश को मंजूरी दे दी। इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त कर दिया गया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बर्खास्तगी का फैसला भविष्य में दिल्ली विश्वविद्यालय, अन्य कॉलेजों या सरकारी सेवाओं में पदों के लिए आवेदन करने में अयोग्यता नहीं माना जाएगा।

इस कार्रवाई के विरोध में नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीएफ) ने शिक्षक के अधिकारों, गरिमा और निष्पक्ष प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं।

राजधानी में छाई धुंध,तीन जगहों पर एक्यूआई 400 पार

नई दिल्ली,साहस समाचार।



राजधानी में मौसमी गतिविधियों के कारण दिन भर धुंध छाई रही। सुबह शाम प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो गई। फरवरी के बाद पहली बार राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 को पार किया है। सीपीसीबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को राजधानी का एक्यूआई 324 जारी किया जबकि यह रविवार को 261 था। सीपीसीबी के अनुसार आने वाले समय में फिलहाल प्रदूषण से राहत की संभावना कम है।

दिल्ली के कुल 58 निगरानी केंद्रों में से 37 पर वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब', 17 पर 'खराब' और तीन पर 'गंभीर' श्रेणी में रही। केवल एक केंद्र पर वायु गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बेहद खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।सीपीसीबी ने बताया कि दिल्ली की हवा में पीएम2.5 प्रमुख प्रदूषक बना हुआ है।

वायु गुणवत्ता के ये आंकड़े दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए लागू प्रतिबंधों के दूसरे दिन सामने आए हैं। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार, राजधानी में तीन से पांच नवंबर तक एक्यूआई 'बेहद खराब' श्रेणी में बने रहने की आशंका है। इसके बाद अगले छह दिनों के दौरान इसमें मामूली सुधार राजधानी में शाम 4 बजे तीन जगहों 400 से अधिक प्रदूषण का स्तर दर्ज किया गया। इसमें जहांगीरपुरी में 436, पंजाबी बाग में 413 तथा रोहिणी में 415 दर्ज किया गया।

कई जगहों पर यह 400 के करीब था। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। सोमवार को राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 29.5 दर्ज किया गया यह सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम था।

राजधानी में नमी का स्तर अधिकतम 100 फीसद तथा न्यूनतम 58 फीसद दर्ज किया गया। मंगलवार को राजधानी में मौसम साफ रहने की संभावना है। राजधानी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चार और सात नवंबर को भी अधिकतम तापमान में कमी होने की संभावना है।

बुधवार से 'यमुना सफारी' का आनंद ले सकेंगे नागरिक

नई दिल्ली,साहस समाचार।



दिल्ली में यमुना पर चलने वाली क्रूज सेवा को आगामी बुधवार से शुरु किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यमुना में क्रूज परिचालन को लेकर चल रहा ट्रायल पूरा हो चुका है। इसलिए बुधवार से इस क्रूज पर दिल्लीवासियों के लिए यमुना सफारी शुरु की जाएगी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में क्रूज की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा किराये को लेकर भविष्य में समीक्षा भी की जाएगी ताकि ज्यादा यात्री क्रूज की सवारी का आनंद ले सकें।

जानकारी के अनुसार बीते सप्ताह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना नदी पर विकसित की जा रही क्रूज सेवा का ट्रायल लिया था। इसके बाद से एक सप्ताह का ट्रायल यमुना में शुरु किया गया था जो पूरा हो गया है। ट्रायल के दौरान यमुना में क्रूज का परिचालन सामान्य रहा जिसके चलते अब आम लोगों के लिए इस सेवा को शुरु किया जा रहा है। बुधवार से दिल्ली में रहने वाले आम लोग इस क्रूज से सफर कर सकेंगे। एक बारी में इस क्रूज पर लगभग 40 लोग सफर कर सकते हैं और इसका किराया अभी 500 रुपये प्रति सवारी रखा गया है। लेकिन भविष्य में इसकी समीक्षा कर किराये को कम किया जा सकता है।

दिल्ली सरकार के अनुसार यह पहल एक आकर्षक पर्यटन स्थल विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोनिया विहार से जगतपुर तक लगभग छह किलोमीटर के जलमार्ग पर विकसित की गई यह क्रूज सेवा दिल्ली में पर्यटन की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी।

इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। नदी के आसपास उपलब्ध सुविधाओं को विकसित करके इस क्षेत्र को एक आकर्षक पर्यटन एवं मनोरंजन स्थल बनाया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत यात्रियों की सुविधा के लिए फूड कियोस्क, रेस्टोरेंट, बच्चों के लिए किड्स ज़ोन और अन्य आवश्यक जनसुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

अधिकारियों के अनुसार 40 यात्रियों की क्षमता वाली क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर स्थित शनि मंदिर तक आने-जाने का पूरा सफर लगभग 35 से 45 मिनट में पूरा करेगी। यात्रियों के लिए तैयार की गई व्यवस्था के अंतर्गत परिसर में प्रवेश शुल्क 50 रुपये और क्रूज की एक पूरी यात्रा का प्रस्तावित शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार, डीडीए, दिल्ली सरकार और दिल्ली पर्यटन के साझा प्रयासों से यह परियोजना साकार हो रही है।

भाजपा ने पदयात्रा निकाल सिख दंगे में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली,साहस समाचार।



1984 के सिख दंगे को लेकर भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर फिर निशाना साधा है। सोमवार को दिल्ली भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने सिख संगत और दंगा पीड़ित परिवारों के सदस्यों के साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब से गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब तक गुरुबाणी का जाप करते हुए श्रद्धांजलि पदयात्रा निकाली। वहां पहुंचने के बाद सिख दंगे में जान गंवाने वालों की स्मृति में मोमबत्तियां जलाई गईं।

सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में सिखों के खिलाफ हुए नरसंहार में लोगों को संगठित तरीके से निशाना बनाया गया था। आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के समर्थित लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि कांग्रेस ने कभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी फिर से सिख समाज के जख्मों को न कुरेदें और देश में अराजकता न फैलाएं।

सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह कहकर नरसंहार को जायज ठहराने की कोशिश की थी कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। राहुल गांधी ने एक नवंबर को रैली निकालने का दिन चुन कर उसी मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा और नौकरियां देने के साथ दोषियों को सजा दिलाने का काम किया, जिसका उदाहरण सज्जन कुमार को मिली सजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन की रैली में किसी भी नेता ने 1984 के सिख दंगे पर एक शब्द नहीं बोला। इस पदयात्रा में पीड़ित परिवारों के सदस्य सरदार करतार सिंह, प्रीति सिंह कौर, जसवीर कौर, भागी कौर, परमजीत कौर, मनप्रीत कौर के साथ भाजपा नेता राजीव बब्बर, मोहनलाल गिहारा, योगिता सिंह, कैलाश जैन आदि शामिल हुए।



संपादकीय

सट्टे का डिजिटल साम्राज्य और कानून की लंबी पहुंच

देवेंद्र सिंह तोमर

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाए जाने की खबर ने एक बार फिर उस काले डिजिटल कारोबार पर बहस को केंद्र में ला दिया है, जिसने तकनीक की रफ्तार का इस्तेमाल कानून से बचने के लिए किया। यह मामला केवल एक व्यक्ति, एक ऐप या कुछ करोड़ रुपये के कथित लेन-देन का मामला नहीं है। इसके पीछे ऑनलाइन सट्टेबाजी का वह पूरा नेटवर्क दिखाई देता है, जिसमें तकनीक, फर्जी पहचान, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशों में बैठे ऑपरेटर और देश के अलग-अलग हिस्सों में फैले एजेंटों का इस्तेमाल होने के आरोप सामने आते रहे हैं।

महादेव ऐप प्रकरण की सबसे गंभीर बात यह है कि इसने दिखा दिया कि अपराध का स्वरूप बदल चुका है। पहले सट्टेबाजी के अड्डे किसी कमरे, दुकान या सुनसान जगह पर चलते थे। आज मोबाइल फोन ही अड्डा है, इंटरनेट ही रास्ता है और डिजिटल भुगतान उसका माध्यम बन सकता है। कुछ क्लिक में हजारों लोग किसी खेल, मैच या घटना पर पैसा लगा सकते हैं। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा नुकसान केवल उस व्यक्ति का नहीं होता जो अपना पैसा गंवाता है। इसके साथ काले धन का प्रवाह, आर्थिक अपराध और युवाओं में तेजी से बढ़ती सट्टेबाजी की प्रवृत्ति भी जुड़ जाती है। सौरभ चंद्राकर को भारत लाया जाना जांच एजेंसियों के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। जांच का उद्देश्य केवल किसी एक आरोपी तक पहुंचना नहीं होना चाहिए। यह पता लगाना जरूरी है कि इस कथित नेटवर्क का वित्तीय ढांचा क्या था, पैसा किन रास्तों से घूमता था, किन लोगों और संस्थाओं के माध्यम से उसका संचालन होता था और इस पूरे तंत्र को संरक्षण या सुविधा किस स्तर पर मिली। सबसे महत्वपूर्ण सवाल डिजिटल सट्टेबाजी के उन स्थानीय नेटवर्कों का है, जो किसी बड़े ऐप का नाम बदलकर या नए प्लेटफॉर्म के जरिए फिर सक्रिय हो जाते हैं। यदि केवल एक ऐप बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर दस नए ऐप आ गए तो कार्रवाई का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। सरकार और जांच एजेंसियों को तकनीकी विशेषज्ञता के साथ ऐसी स्थायी व्यवस्था विकसित करनी होगी, जिससे अवैध सट्टेबाजी के डिजिटल नेटवर्क की पहचान, भुगतान चैनलों की निगरानी और संदिग्ध धन के प्रवाह को समय रहते रोका जा सके।

इस मामले में विदेश से आरोपी को भारत लाना एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है-आर्थिक अपराध करने वाला व्यक्ति विदेश में बैठकर हमेशा कानून की पहुंच से बाहर नहीं रह सकता। लेकिन प्रत्यर्पण किसी जांच की अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत है। अदालत में आरोपों को प्रमाणित करने के लिए मजबूत और ठोस साक्ष्य चाहिए। जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है कि कार्रवाई तथ्यों और कानून के आधार पर हो और किसी निर्दोष व्यक्ति को केवल प्रचार या राजनीतिक आरोपों के आधार पर कठघरे में खड़ा न किया जाए।

महादेव प्रकरण से देश को एक बड़ा सबक लेना चाहिए। डिजिटल भारत में अपराध भी डिजिटल हो रहा है। इसलिए केवल पुराने कानूनों और पारंपरिक जांच पद्धतियों के भरोसे इस चुनौती का सामना नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, क्रिप्टो, डिजिटल भुगतान और विदेशी सर्वरों के बीच बनने वाले नए अपराध तंत्र को समझने के लिए जांच एजेंसियों को तकनीकी रूप से और मजबूत करना होगा। यह भी उतना ही जरूरी है कि समाज इस समस्या को केवल पुलिस और सरकार की समस्या न माने। युवाओं में आसान और तेज पैसा कमाने का भ्रम ऑनलाइन सट्टे का सबसे बड़ा हथियार है। विज्ञापन, सोशल मीडिया और प्रभावशाली चेहरों के माध्यम से जब सट्टेबाजी को मनोरंजन या कमाई के अवसर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तब उसके सामाजिक परिणाम कहीं ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। महादेव ऐप मामले में अब देश की निगाह अदालत और जांच एजेंसियों पर है। भारत लौटे आरोपी से पूछताछ से यदि पूरे नेटवर्क की कड़ियां जुड़ती हैं, धन के स्रोत और गंतव्य सामने आते हैं तथा जिम्मेदार लोगों तक कानून पहुंचता है, तभी यह कार्रवाई सार्थक मानी जाएगी।

गरीबी से मुक्ति: भारत में उम्मीद का नया उजाला



ललित गर्ग

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में अत्यधिक निर्धनता की दर 27.1 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई। इसी अवधि में 4.20 डॉलर प्रतिदिन की अंतरराष्ट्रीय निर्धनता सीमा के अंतर्गत आने वाली आबादी का अनुपात 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत हो गया। इसका अर्थ है कि लगभग 49.6 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए।



किसी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति का आकलन केवल उसकी आर्थिक विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक विस्तार अथवा वैश्विक आर्थिक रैंकिंग से नहीं किया जा सकता। विकास की सार्थकता तब सिद्ध होती है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, निर्धनता का दायरा सिमटे, सामान्य नागरिक के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि का संचार हो, गरीबी का कलंक मिटे तथा आर्थिक अवसरों पर सबका समान अधिकार स्थापित हो। इस दृष्टि से भारत में गरीबी और निर्धनता के स्तर में आई उल्लेखनीय गिरावट एक ऐतिहासिक उपलब्धि और नए भारत के निर्माण का शुभ संकेत है। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट में भारत की इस प्रगति को वैश्विक स्तर पर गरीबी में आई सबसे तेज गिरावटों में से एक माना जाना इस उपलब्धि को और महत्वपूर्ण बनाता है। यह केवल आर्थिक आंकड़ों का परिवर्तन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में गरीबी उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों का यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है, एक शुभ एवं श्रेयस्कर भविष्य की आहट है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में अत्यधिक निर्धनता की दर 27.1 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई। इसी अवधि में 4.20 डॉलर प्रतिदिन की अंतरराष्ट्रीय निर्धनता सीमा के अंतर्गत आने वाली आबादी का अनुपात 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत हो गया। इसका अर्थ है कि लगभग 49.6 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए। वर्ष 2028 तक इस अनुपात के 12.1 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। ये आंकड़े भारत की आर्थिक और सामाजिक यात्रा में एक बड़े परिवर्तन के प्रमाण हैं। विशेष बात यह है कि भारत ने इतनी बड़ी आबादी, व्यापक सामाजिक विविधता और कोविड जैसी वैश्विक महामारी की चुनौतियों के बावजूद निर्धनता कम करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, यह मोदी सरकार की युगान्तरकारी जन-कल्याण योजनाओं एवं गरीबी उन्मूलन के संकल्पों का ही परिणाम है। इस परिवर्तन के पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि विकास को जनकल्याण से जोड़ने की नीति भी महत्वपूर्ण रही है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, हर घर जल, आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना और मुफ्त खाद्यान्न वितरण जैसी योजनाओं ने निर्धन परिवारों के जीवन में व्यापक बदलाव लाने का काम किया है। इन योजनाओं की विशेषता यह है कि इन्होंने गरीबी को केवल आय की कमी के रूप में नहीं देखा, बल्कि आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, भोजन और वित्तीय समावेशन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से जोड़कर उसका समाधान करने का प्रयास किया है।

किसी निर्धन परिवार को पक्का मकान मिलना केवल आवास की उपलब्धता नहीं, बल्कि उसे संपत्ति, सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करना है। घर में बिजली, शौचालय और नल से जल की सुविधा उपलब्ध होना उसके जीवन की गुणवत्ता में बुनियादी परिवर्तन लाता है। जनधन खातों और आधार जैसी व्यवस्थाओं ने नागरिकों को वित्तीय एवं वैधानिक पहचान प्रदान की है। आयुष्मान भारत ने स्वास्थ्य संकट के समय गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने का आधार तैयार किया है। विश्व बैंक ने गरीबी में कमी के प्रमुख कारणों में उपभोग में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का विस्तार, विशेषकर महिलाओं की रोजगार में बढ़ती भागीदारी और खाद्य सब्सिडी सहित सामाजिक कल्याणकारी हस्तांतरणों की भूमिका को रेखांकित किया है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच रोजगार में लगभग 13.4 करोड़ लोगों की वृद्धि होना भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती आर्थिक सक्रियता परिवारों की आय बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक आत्मनिर्भरता और निर्णय क्षमता को भी मजबूत करती है। ग्रामीण भारत में निर्धनता की तेज गिरावट ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक अंतर को भी कम करने में योगदान दिया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण संकेतक गिनी सूचकांक है, जिसके माध्यम से आय अथवा उपभोग के वितरण में असमानता का आकलन किया जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत का उपभोग आधारित गिनी सूचकांक 23 तक पहुंचा है, जो अपेक्षाकृत कम असमानता का संकेत देता है। यह अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की तुलना में भारत की बेहतर स्थिति को दर्शाता है। हालांकि यहां यह समझना आवश्यक है कि उपभोग आधारित गिनी सूचकांक समाज में संपत्ति, आय और अवसरों की समग्र असमानता का पूरा चित्र प्रस्तुत नहीं करता। इसलिए गरीबी में कमी को आर्थिक समानता की पूर्ण उपलब्धि मान लेना उचित नहीं होगा। यही वह बिंदु है, जहां भारत की विकास यात्रा का आलोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। एक ओर करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, दूसरी ओर समाज में संपत्ति और आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। उच्च आय वर्ग और सामान्य मेहनतकश नागरिक के बीच जीवन की सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अवसरों का अंतर अभी भी व्यापक है। गुणवत्तापूर्ण रोजगार की कमी, असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की असुरक्षा, युवाओं में बेरोजगारी, कृषि पर निर्भर परिवारों की सीमित आय और महिलाओं को समान पारिश्रमिक न मिलना ऐसे प्रश्न हैं, जिनका समाधान किए बिना समतामूलक समाज की कल्पना अधूरी रहेगी। गरीबी का कम होना और अमीरी-गरीबी के बीच की खाई का कम होना दो अलग-अलग स्थितियां हैं। पहली उपलब्धि उत्साह देती है, लेकिन दूसरी चुनौती पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक है।

भारत को अब ऐसी विकास नीति की आवश्यकता है, जिसमें आर्थिक प्रगति का लाभ केवल कुछ क्षेत्रों, वर्गों अथवा उद्योगों तक सीमित न रहे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास, छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन, कृषि का आधुनिकीकरण, श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। कर व्यवस्था में न्यायपूर्ण संतुलन, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में निवेश और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शिता भी आवश्यक है। विकास का वास्तविक उद्देश्य अवसरों की समानता पैदा करना होना चाहिए, न कि केवल आर्थिक आंकड़ों में ऊंचाई हासिल करना। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में गरीबी में कमी की यह उपलब्धि विशेष महत्व रखती है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब आर्थिक शक्ति के साथ सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और अवसरों की समानता भी सुनिश्चित हो। गरीबी-मुक्त भारत का सपना केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि रोजगार, उद्यमिता, शिक्षा, सामाजिक सहभागिता और न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था के समन्वय से साकार होगा। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट भारत में गरीबी से मुक्ति की ओर बढ़ते कदमों और करोड़ों जीवन में फैलती खुशहाली की ऐसी उजली तस्वीर प्रस्तुत करती है, मानो दीपावली के पर्व पर विकास के दीप जल उठे हों। यह केवल आंकड़ों की रोशनी नहीं, बल्कि उन करोड़ों परिवारों के जीवन में उम्मीद, आत्मविश्वास और सम्मान का उजाला है, जो अभावों के अंधकार से निकलकर समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। सचमुच, इस बार दीपावली के दीपों में नए भारत की प्रगति और गरीबों के जीवन में आए उजास की चमक भी दिखाई दे रही है।

निस्संदेह, गरीबी के मोर्चे पर भारत की यह सफलता नए भारत, समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में करोड़ों लोगों को निर्धनता के दायरे से बाहर लाना एक उल्लेखनीय स्थान रखता है। लेकिन इस उपलब्धि का अगला चरण आर्थिक असमानता की खाइयों को पाटना और विकास की रोशनी को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना होना चाहिए। विकसित भारत की पहचान केवल उसकी आर्थिक समृद्धि से नहीं, बल्कि इस बात से होगी कि वहां कोई व्यक्ति अभाव, भुखमरी, अशिक्षा और असहायता में जीवन जीने को विवश न हो। 2047 का भारत तभी वास्तविक अर्थों में विकसित और समृद्ध होगा, जब उसकी प्रगति का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचेगा और आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक समरसता एवं समानता भी उसकी पहचान बनेगी। यही नए भारत का स्वप्न है और यही उसकी विकास यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी भी।

हाईवे के किनारे सजी देशी उत्पादों की दुकानें



डॉ. सत्यवान सौरभ

राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता सदियों पुराना है। यहाँ की मिट्टी, जलवायु, वनस्पति और पारंपरिक जीवनशैली ने खान-पान की ऐसी समृद्ध संस्कृति विकसित की है, जिसकी पहचान आज भी देश के कोने-कोने में है। इसी संस्कृति का एक जीवंत दृश्य हमें तब दिखाई देता है, जब हम राजस्थान के किसी हाईवे से गुजरते हैं और सड़क किनारे बोरी बिछाकर बैठे ग्रामीण महिला-पुरुषों को देखते हैं। उनके सामने कैर, बेर, काचरी, सांगरी और अनेक देशी उत्पाद सजे होते हैं। पहली नजर में यह एक सामान्य-सी ग्रामीण बाजार व्यवस्था लग सकती है, लेकिन इसके पीछे मेहनत, संघर्ष, आत्मनिर्भरता और परिवार के प्रति जिम्मेदारी की एक बड़ी कहानी छिपी होती है।

ये लोग दो-तीन दिन तक मेहनत करके जंगलों, खेतों और आसपास के प्राकृतिक क्षेत्रों से मौसमी उत्पाद इकट्ठा करते हैं। इसके बाद उन्हें साफ-सुथरा करके बेचने के लिए हाईवे किनारे पहुँचते हैं। इनके पास कोई बड़ी दुकान नहीं होती, न ही कोई आकर्षक बोर्ड या आधुनिक व्यापारिक व्यवस्था। एक बोरी ही इनकी दुकान बन जाती है और सड़क किनारे की थोड़ी-सी जगह इनका बाजार।

इनकी दुकान पर केवल कैर ही नहीं मिलता, बल्कि राजस्थान की पारंपरिक खाद्य संस्कृति का पूरा खजाना दिखाई देता है। बेर, काचरी, मतीरे के बीज, तुम्बे के बीज, हरी और सूखी ग्वारफली, सूखे काचर, सूखे कैर, सांगरी और कई अन्य मौसमी उत्पाद इनके पास उपलब्ध होते हैं। ये वे चीजें हैं, जिनका राजस्थान के पारंपरिक खान-पान में विशेष महत्व रहा है। विशेषकर कैर-सांगरी जैसी सब्जियाँ आज राजस्थान की पहचान बन चुकी हैं और देश-विदेश तक अपनी लोकप्रियता रखती हैं।



इन ग्रामीण विक्रेताओं की कार्यशैली भी अपने आप में दिलचस्प है। वे सड़क किनारे बोरी बिछाकर सामान फैला देते हैं। राहगीर रुकते हैं, उत्पादों को देखते हैं, गुणवत्ता के बारे में पूछते हैं और फिर मोलभाव शुरू होता है। विक्रेता अपनी मेहनत का मूल्य बताते हैं और ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार भाव तय करने का प्रयास करता है। कई बार थोड़ी-सी बातचीत के बाद सौदा तय हो जाता है। सामान बिकने पर विक्रेता के चेहरे पर जो संतोष दिखाई देता है, वह किसी बड़े व्यापारिक लाभ से कम महत्वपूर्ण नहीं है।

दिनभर सड़क किनारे बैठकर ग्राहक का इंतजार करना आसान काम नहीं है। गर्मी, धूल, तेज धूप, सर्दी और बदलते मौसम के बीच ये लोग अपने उत्पाद बेचते हैं। कभी अच्छी बिक्री होती है तो कभी दिनभर इंतजार करने के बावजूद बहुत कम सामान बिक पाता है। फिर भी वे अगले दिन नई उम्मीद के साथ अपनी छोटी-सी दुकान सजाने पहुँच जाते हैं। बताया जाता है कि इनमें से कई लोग दिनभर की मेहनत के बाद लगभग 500 से 700 रुपये तक कमा पाते हैं। किसी बड़े शहर के बाजार में यह रकम शायद बहुत छोटी लगे, लेकिन इन परिवारों के लिए यही कमाई घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों का आधार बनती है। इस छोटी-सी आय के पीछे कई दिनों की मेहनत, प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी और बाजार तक पहुँचने का संघर्ष शामिल होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है कि ये लोग केवल सामान बेचने वाले छोटे विक्रेता नहीं हैं, बल्कि हमारी पारंपरिक खाद्य संस्कृति के संवाहक भी हैं। आज जब बाजार में पैकेटबंद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का चलन तेजी से बढ़ रहा है, तब ये ग्रामीण विक्रेता हमें प्रकृति से जुड़े पारंपरिक उत्पादों की याद दिलाते हैं। उनके पास मिलने वाली काचरी, कैर, सांगरी और अन्य मौसमी चीजें हमारी पुरानी रसोई और ग्रामीण जीवनशैली का हिस्सा रही हैं। राजस्थान के ग्रामीण परिवारों ने सीमित संसाधनों और कठिन जलवायु के बीच खान-पान की ऐसी परंपराएँ विकसित की हैं, जिनमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उपलब्ध खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता रहा है। कैर-सांगरी, काचरी की सब्जी और सूखे देशी उत्पाद इसी अनुभव और परंपरा की देन हैं। इनका स्वाद केवल भोजन का स्वाद नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है।

दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम अक्सर बड़े शोरूम, मॉल और ऑनलाइन बाजारों से खरीदारी करने में तो रुचि दिखाते हैं, लेकिन सड़क किनारे बैठे इन छोटे विक्रेताओं की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। कई बार हम उनके सामान की कीमत पर बहुत अधिक मोलभाव करते हैं, जबकि यह भूल जाते हैं कि उनके लिए कुछ रुपये का अंतर भी महत्वपूर्ण हो सकता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि स्थानीय उत्पाद खरीदने का अर्थ केवल कम कीमत पर सामान प्राप्त करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है स्थानीय मेहनत को सम्मान देना, ग्रामीण परिवारों की आय में योगदान करना और छोटे स्तर पर चल रही पारंपरिक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। यदि हम हाईवे पर यात्रा करते समय ऐसे किसी विक्रेता को देखें, तो कुछ समय निकालकर उसके पास जरूर रुकें। उत्पादों की जानकारी लें, अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी करें और उचित मूल्य चुकाएँ। संभव हो तो आसपास के लोगों को भी ऐसे विक्रेताओं से खरीदारी करने के लिए प्रेरित करें। हमारी थोड़ी-सी पहल इन परिवारों के लिए बड़ी राहत बन सकती है।

हालाँकि, खरीदारी करते समय स्वच्छता और गुणवत्ता का ध्यान रखना भी जरूरी है। उत्पादों की ताजगी, सफाई और उचित भंडारण देखकर ही खरीदारी करनी चाहिए। किसी भी उत्पाद को बिना जाँच के शत-प्रतिशत शुद्ध मानने के बजाय उसकी वास्तविक गुणवत्ता सुनिश्चित करना उपभोक्ता के हित में है। सरकार और स्थानीय प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे छोटे विक्रेताओं को सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध करवाएँ। उन्हें अनावश्यक परेशानियों से बचाया जाए और उनके पारंपरिक उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएँ। स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण बाजारों और स्थानीय उत्पाद मेलों के माध्यम से भी इनकी आय बढ़ाने की संभावनाएँ विकसित की जा सकती हैं। आज आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की चर्चा हर स्तर पर हो रही है। ऐसे में हाईवे किनारे बैठा यह छोटा विक्रेता भी आत्मनिर्भरता का एक सशक्त उदाहरण है। वह किसी पर निर्भर रहने के बजाय अपनी मेहनत से आजीविका अर्जित कर रहा है। उसके पास न बड़ी पूँजी है, न आधुनिक संसाधन, लेकिन उसके पास मेहनत करने का साहस और अपने परिवार को पालने का संकल्प जरूर है। अंततः सवाल केवल इतना नहीं है कि हमें कैर, काचरी या सांगरी कहाँ से खरीदनी चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या हम उस मेहनतकश इंसान की मेहनत का सम्मान करने के लिए तैयार हैं, जो अपनी छोटी-सी पूँजी और सीमित संसाधनों के साथ जीवन की लड़ाई लड़ रहा है? आइए, जब भी हाईवे पर ऐसे ग्रामीण विक्रेता दिखाई दें, तो उनकी दुकान पर जरूर रुकें। जरूरत का सामान खरीदें, उचित दाम दें और उनकी मेहनत को सम्मान दें।

दुनिया भर के युवाओं में क्यों बढ़ रहा असंतोष?

दुनिया तेजी से बदल रही है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं और अर्थव्यवस्थाओं के विकास के दावे किए जा रहे हैं। इसके बावजूद दुनिया के अनेक देशों में युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। रोजगार की कमी, महँगाई, महँगा आवास, शिक्षा का बढ़ता खर्च और आर्थिक असुरक्षा ने युवाओं के सामने गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। यही कारण है कि उनकी चिंताएँ अब व्यक्तिगत परेशानी तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनती जा रही हैं। हाल के दिनों में जर्मनी और फ्रांस सहित यूरोप के कई देशों में युवाओं के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों ने इस समस्या को दुनिया के सामने रखा है। इन आंदोलनों में युवाओं ने बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर, किफायती आवास और जीवनयापन की बढ़ती लागत से राहत देने की माँग की है। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के आँकड़े और आम नागरिकों के जीवन की वास्तविक परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं होतीं।



अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की अगस्त 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में दुनिया के युवाओं की बेरोजगारी दर बढ़कर 12.4 प्रतिशत हो गई। लगभग 6.7 करोड़ युवा बेरोजगार थे। रिपोर्ट यह भी बताती है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त करना पहले की तुलना में कठिन हुआ है। उत्तरी अमेरिका में युवा बेरोजगारी की दर वर्ष 2023 के 8.3 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 9.8 प्रतिशत हो गई। उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप में यह दर लगभग 15 प्रतिशत रही।

इन आँकड़ों का अर्थ केवल इतना नहीं है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। इसके पीछे एक बड़ी समस्या रोजगार की गुणवत्ता भी है। अनेक युवा अपनी योग्यता के अनुरूप काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ को अस्थायी रोजगार मिलता है, जबकि दूसरे कम वेतन पर काम करने को विवश हैं। नौकरी मिलने के बाद भी यह निश्चित नहीं होता कि उनकी आय नियमित रहेगी और भविष्य सुरक्षित होगा। जब शिक्षा पूरी करने के बाद भी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, तो युवाओं में निराशा बढ़ना स्वाभाविक है। युवाओं की आर्थिक चिंताओं का दूसरा बड़ा कारण जीवनयापन की बढ़ती लागत है। भोजन, परिवहन, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और आवास पर होने वाला खर्च लगातार उनके बजट को प्रभावित करता है। विशेष रूप से बड़े शहरों में किराये की ऊँची दरों के कारण कम आय वाले युवाओं के लिए स्वतंत्र रूप से रहना कठिन होता जा रहा है। यूरोप में हाल के प्रदर्शनों के दौरान आवास और महँगाई का मुद्दा प्रमुखता से उठा। जब किसी युवा की आय का बड़ा हिस्सा केवल किराया और आवश्यक वस्तुओं पर खर्च हो जाता है, तो बचत करना, परिवार शुरू करना अथवा अपने भविष्य के लिए निवेश करना कठिन हो जाता है। यह समस्या केवल यूरोप तक सीमित नहीं है। भारत सहित अनेक विकासशील देशों के बड़े शहरों में भी युवाओं को शिक्षा, रोजगार और आवास के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आर्थिक स्वतंत्रता का सपना तब अधूरा रह जाता है, जब नियमित आमदनी के बावजूद बुनियादी जरूरतें पूरी करना चुनौती बन जाए। 31 अक्टूबर 2026 को जर्मनी के 34 शहरों में युवाओं के नेतृत्व में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ाने, जीवनयापन की लागत कम करने तथा अनिवार्य सैन्य सेवा का विरोध करने जैसी माँगें उठाईं। अधिकांश प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, हालाँकि कुछ स्थानों पर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएँ भी हुईं। फ्रांस में भी युवाओं और अन्य सामाजिक समूहों ने शिक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं, महँगाई और रोजगार की समस्याओं को लेकर विरोध जताया। इन आंदोलनों में एक साझा भावना दिखाई देती है। युवाओं को लगता है कि उनकी समस्याओं को पर्याप्त गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है और नीतियाँ बनाते समय उनकी आवश्यकताओं को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता।

इन घटनाओं को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानकर नहीं देखा जाना चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र में अपनी बात रखने का एक माध्यम है। सरकारों को हिंसा रोकने के साथ उन आर्थिक और सामाजिक कारणों पर भी विचार करना चाहिए, जिनसे असंतोष पैदा हो रहा है।

विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली हैं राहुल: नवीन

कोलकाता, एजेंसी।



भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में 'अराजकता' फैलाने वालों का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रही विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं।

नवीन ने 'वोट चोरी' के खिलाफ विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के अभियान का जवाब देने के लिए कोलकाता में एक मार्च का नेतृत्व करने के बाद एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने दिल्ली को 'राहुल मुक्त' बनाने का आह्वान भी किया।

नवीन ने इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया।

भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि इन ताकतों ने नेपाल और भारत के अन्य पड़ोसी देशों में अशांति फैलाने की साजिश रची थी।

भाजपा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं और 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के अभियान के जवाब में देशभर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च शुरू किए हैं। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने इन मुद्दों को लेकर रविवार को नयी दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली की थी।

इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक 'जन महाभियोग' भी आयोजित किया गया था।

कोलकाता में नवीन ने कॉलेज स्ट्रीट से मध्य कोलकाता के धर्मतला तक मार्च का नेतृत्व किया, इसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य सहित पार्टी के कई अन्य नेता शामिल हुए।

भाजपा अध्यक्ष ने धर्मतला में रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया, "राहुल गांधी उन ताकतों के हाथों की कठपुतली हैं, जिन्होंने नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों में अशांति फैलाने की साजिश रची। वह देशभर में अराजकता फैलाने वाली ताकतों का नेतृत्व कर रहे हैं।"

नवीन ने तंज कसते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने 'प्रतीकात्मक संसद' आयोजित कर अपने बेटे राहुल गांधी की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पूरी कर दी है।

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी के पास कोई दृष्टिकोण नहीं है। कांग्रेस के पूरी तरह राजनीतिक रूप से खत्म होने के लिए वही जिम्मेदार होंगे।"

नवीन ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और कहा कि राज्य में हार के बाद वह दिल्ली में 'आंसू बहा रही हैं'। नवीन ने कहा, जिस तरह बंगाल को ममता मुक्त किया गया है, उसी तरह हम दिल्ली को राहुल मुक्त करेंगे। हमने 2014, 2019 व 2024 में कांग्रेस और राहुल गांधी को हराया है। हम 2029 में भी ऐसा ही करेंगे। उनके इस बयान पर रैली में मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं। उन्होंने कांग्रेस नेता के राजनीतिक रुख पर भी सवाल उठाए।

नवीन ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की थी, लेकिन अब वह उसी पार्टी के नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी यहां आए थे और उन्होंने ममता बनर्जी सरकार में भ्रष्टाचार तथा कुशासन के खिलाफ बयान दिए थे। अब दोनों एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं।"

नवीन ने दावा किया कि अगर कांग्रेस और राहुल गांधी ने अपनी चुनावी हार से सबक लिया होता, तो वे निर्वाचन आयोग पर निराधार आरोप नहीं लगाते।

उप्र विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आकलन कर रहा है जदयू

नई दिल्ली, एजेंसी। जनता दल-यूनाइटेड (जद-यू) ने सोमवार को कहा कि वह उत्तर प्रदेश के उन निर्वाचन क्षेत्रों का आकलन कर रहा है, जहां वह 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ सके, साथ ही यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के एक घटक के रूप में चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है। जद(यू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि पार्टी ने पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है और उसके उम्मीदवार विधानसभा के लिए निर्वाचित भी हुए हैं।

उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जद(यू) उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। उन्होंने कहा, हमने पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है और वहां हमारे विधायक चुने गए हैं। पार्टी लंबे समय से बिहार के बाहर अन्य राज्यों में भी काम कर रही है। हमारा संगठनात्मक ढांचा काफी अच्छा है। प्रसाद ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। हम उन निर्वाचन क्षेत्रों का आकलन कर रहे हैं जहां हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके बाद उन निर्वाचन क्षेत्रों पर निर्णय लिया जाएगा जहां हम चुनाव लड़ सकते हैं। इन टिप्पणियों से एक दिन पहले ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और जद(यू) प्रमुख नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के साथ, वाराणसी में आयोजित जद(यू) के राज्य-स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया था।

राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी की विधान परिषद सदस्यता रद्द की जाए: जनसुराज पार्टी

पटना, एजेंसी।

प्रशांत किशोर नीत जनसुराज पार्टी ने बतौर निर्दलीय बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी की सदस्यता सोमवार को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि दोनों विधान पार्षदों ने स्वयं भाजपा में शामिल होने की बात स्वीकार की है जो संविधान और दल-बदल कानून का उल्लंघन है।

जनसुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना तथा रामबली सिंह चंद्रवंशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने विधान परिषद के सभापति राम बचन राय से मुलाकात की और अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ दोनों विधान पार्षदों (एमएलसी)को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका सौंपी।

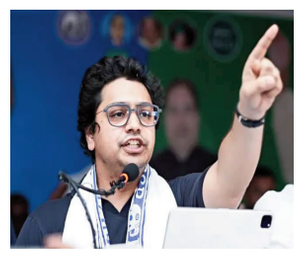
पूर्व विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी ने बाद में कहा कि राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण की, उसे पूरे देश ने देखा है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, अतीत में मेरी भी विधान परिषद की सदस्यता समाप्त की गई थी। इसलिए मैं नियम-कानून को बेहतर तरीके से जानता और समझता हूं। हमने पार्टी की ओर से विधान परिषद के सभापति डॉ. रामबचन राय को आवेदन देकर दोनों नेताओं की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। चंद्रवंशी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 48 घंटे के भीतर ही दोनों नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया।

चक्रवात मुरासु के लिए तैयारियां जारी

अमरावती, एजेंसी। एक हफ्ते के भीतर आने वाले दूसरे भीषण चक्रवात का सामना करने की तैयारी कर रहे देश के पूर्वी तटीय राज्यों में भारी बारिश हुई और सोमवार को कई उड़ानें रद्द कर दी गईं, आपदा राहत टीमों को अलर्ट पर रखा गया और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 'मुरासु' चक्रवात - जिसका अर्थ 'युद्ध का नगाड़ा' होता है - के सोमवार आधी रात से मंगलवार तड़के के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और नरसापुर के बीच तट पर दस्तक देने की आशंका है। इस दौरान हवा की गति 100-110 किमी प्रति घंटा रहने और झोंकों के साथ 120 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। सोमवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, तिरुपति और विशाखापत्तनम हवाईअड्डों पर कम से कम 19 घरेलू उड़ानें रद्द की।

सपा भाजपा की 'बी' टीम है : आकाश

सहारनपुर (उप्र), एजेंसी।



बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बी टीम करार देते हुए दावा किया कि (सपा प्रमुख) अखिलेश यादव की राजनीति की कोई दिशा तय नहीं है।

बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे आनन्दज ने सहारनपुर के सोराणा में एक जनसभा में कहा कि अखिलेश यादव कभी पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) में पंडितों की बात करते हैं तो कभी पिछड़ों की। उन्होंने तंज किया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की 'डबल इंजन' की सरकार है, इसलिए तेल ज्यादा पीती है । उन्होंने सपा की तरह भाजपा की सरकार में भी "जंगल राज का आरोप लगाया। आनन्द ने सभा में भाजपा और सपा के बीच रिश्ता होने का दावा करते हुए कहा, ''समाजवादी पार्टी ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य परिमल नाथवानी के पुत्र धनराज नाथवानी को राज्यसभा चुनाव में टिकट दिया और वह जीते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपने एक बयान में अखिलेश यादव को अपना दोस्त बताते हुए कहा था कि वह समय-समय पर उनकी मदद करते रहते हैं। बसपा नेता ने दावा किया, पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार न तो शिक्षा दे पाई, न हमारी बहन-बेटियों को सुरक्षा दे पाई और न ही हमारे युवाओं को रोजगार दे पाई।

केंद्र व जम्मू-कश्मीर के बीच अविश्वास के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार : महबूबा

श्रीनगर, एजेंसी।



पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को केंद्र और जम्मू-कश्मीर के बीच 'अविश्वास' के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस क्षेत्र की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कश्मीर के मुद्दे पर अक्सर अपना रुख बदलती रही है।

कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा, "इस संदेह के माहौल के लिए कौन जिम्मेदार है? 79 साल पहले भारत आजाद हुआ था और 79 साल पहले ही जम्मू-कश्मीर भारत में शामिल हुआ था।

उस विलय पर (नेकां संस्थापक) शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हस्ताक्षर किए थे। जम्मू-कश्मीर के मुस्लिम बहुल राज्य होने के बावजूद, उन्होंने भारत के साथ जुड़ने का फैसला किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस विलय के कुछ ही वर्षों के भीतर, नेकां ने अपना रुख बदल लिया और जनमत संग्रह की मांग करने लगी।

उन्होंने कहा, "यह भ्रम और संदेह आपने (नेशनल कॉन्फ्रेंस) ही लोगों के मन में पैदा किया। 22 साल तक आपने पाकिस्तान में जनमत संग्रह कराने की मांग की और फिर अचानक (1975 में) दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार कर ली।

चक्रवात मुरासु के प्रभाव को लेकर सतर्क रहें अधिकारी : नायडू

अमरावती, एजेंसी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने चक्रवात मुरासु के मद्देनजर सोमवार को अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। मुरासु के प्रभाव से राज्य के दक्षिणी तटीय आंध्र और रायलसीमा जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है।

एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चक्रवात मुरासु का राज्य के तट पर सीमित प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि मौसम के पूर्वानुमानों के अनुसार, इसकी हवा की गति और बारिश की तीव्रता चक्रवात अर्नब की तुलना में कम रहने की उम्मीद है।

नायडू ने प्रशासन को दक्षिणी तटीय आंध्र और रायलसीमा जिलों में मध्यम से भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया।

संविधान राष्ट्र की आत्मा है: ओम बिरला

चंडीगढ़, एजेंसी।



लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कहा कि भारत का संविधान केवल शासन-व्यवस्था का एक ढांचा नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्र की आत्मा समाहित है और यह राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक के रूप में कार्य करता है।

लोकसभा अध्यक्ष ने रेखांकित किया कि संविधान करोड़ों नागरिकों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को समाहित करता है। उन्होंने कहा, ''संविधान से प्रेरित होकर, हमारा सामूहिक प्रयास यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित होना चाहिए कि शासन और प्रशासन जनसेवा पर आधारित हों।

लोकसभा अध्यक्ष ने रेखांकित किया कि सहमति और असहमति हमेशा से हमारे लोकतंत्र की ताकत रही हैं।

बिरला ने हरियाणा के पंचकूला में, 'संविधान पखवाड़ा' के तहत हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित 'जन प्रतिनिधि सम्मेलन' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, ''लोकतंत्र में सहमति और असहमति, दोनों का सम्मान किया जाना चाहिए। विचारों की विविधता नए दृष्टिकोण प्रदान करती है, जबकि सामूहिक प्रयास राष्ट्र और राज्य को आगे बढ़ाते हैं।''

इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, हरियाणा के कई मंत्री, और विभिन्न दलों के मौजूदा तथा पूर्व विधायक मौजूद थे।

हरियाणा अपनी स्थापना के 60 साल पूरे कर रहा है। इसे रेखांकित करते हुए बिरला ने कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद राज्य की विकास यात्रा कड़ी मेहनत, साहस और सामूहिक प्रयासों का एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर से लेकर संसद तक, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी और जुड़ाव ही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।

बिरला ने कहा कि भारत की व्यापक भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक विविधता के बावजूद संसदीय लोकतंत्र को अपनाना, हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का प्रमाण है।

लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम में मौजूद कई मौजूदा और पूर्व विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी है कि वे जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को सदन तक पहुंचाएं, जनहित में कानून बनाएं और लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करें।

सार समाचार

बुजुर्ग चाचा-चाची की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

बागेश्वर,एजेंसी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की बैजनाथ पुलिस ने नरगवाड़ी गांव में लोहे की रॉड से बुजुर्ग दंपति की कथित हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे की खून से सनी रॉड भी बरामद कर ली गई है।बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) जितेन्द्र कुमार मेहरा ने सोमवार को इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि रविवार रात को करीब 8:30 बजे डायल 112 पर एक ग्रामीण निखिल खोलिया ने सूचना दी कि गांव में पूरन चंद्र खोलिया के घर झगड़ा हो रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि गोविंद बल्लभ खोलिया ने अपने चाचा पूरन चंद्र खोलिया (70) और चाची भगवती देवी (62) के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है।

केरलम राज्य वन्यजीव बोर्ड के पुनर्गठन पर विवाद

तिरुवनंतपुरम,एजेंसी। केरलम राज्य वन्यजीव बोर्ड के पुनर्गठन में सत्ताधारी गठबंधन (यूडीएफ) समर्थित प्रमुख पर्यावरणविदों और संरक्षण कार्यकर्ताओं को बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। बोर्ड में कुछ ऐसे सदस्यों के चयन पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिन पर पर्यावरणविदों द्वारा अतीत में वन और वन्यजीव संरक्षण पहलों का विरोध करने के आरोप लगे हैं।

इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं और वन एवं वन्यजीव मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके विधायी सदस्यों में केरल कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के प्रतिनिधि शामिल हैं।

सपा जब भी सत्ता में आई, उप्र में तबाही लाई : योगी

गोंडा (उप्र), एजेंसी।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को प्रदेश के लिये 'श्राप' करार हुए सोमवार को कहा कि सपा जब भी सत्ता में आई, उत्तर प्रदेश में तबाही लाई।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उसके (सपा के) शासन में दंगे, कर्फ्यू और अपराध का बोलबाला था तथा पर्व-त्योहारों से पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सोमवार को गोंडा के छपिया विकासखंड की ग्राम पंचायत तेजपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गौरा और मनकापुर विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी 520 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 69 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क, शिक्षा और पुलों से जुड़ी इन परियोजनाओं के साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र और अन्य सामग्री भी वितरित की। सपा पर निशाना साधते हुए आदित्यनाथ ने कहा, "समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में गोंडा में अनाज का सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। यह पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए एक 'श्राप' है, और जब भी यह (सत्ता में) आई है, इसने केवल अराजकता ही फैलाई है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा में बाधाएं खड़ी की जाती थीं, जबकि अब गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच साढ़े चार करोड़ श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने दो नवंबर 1990 की घटना याद दिलाते हुए कहा कि इसी दिन अयोध्या में तत्कालीन सरकार ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाई थीं। उन्होंने कहा कि सपा ने रामभक्तों को गोलियों से लहूलुहान किया, जबकि भाजपा सरकार ने रामभक्तों पर पुष्पवर्षा कर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले विकास का मतलब केवल सैफई था। अब सभी 75 जिलों तक योजनाएं पहुंच रही हैं। गोंडा के लिए साढ़े नौ वर्षों में 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक और पूरे देवीपाटन मंडल के लिए लगभग 50 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार वर्ष की सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, वन और कारागार सहित विभिन्न विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण और बिना परीक्षा सीधी भर्ती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों को भी पुलिस उपाधीक्षक और खेल अधिकारी सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं।

मणिपुर के पूर्व मंत्री चलतोलियन अमो कांग्रेस में शामिल

नई दिल्ली, एजेंसी। मणिपुर के पूर्व मंत्री चलतोलियन अमो और पूर्व राजस्व अधिकारी डी. पी. हाओकिप सोमवार को यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। अमो मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के टिपाईमुख विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रह चुके हैं। वह 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के तौर पर टिपाईमुख सीट से चुनाव हार गए थे। वह पहली बार 1995 में विधायक बने थे। अमो ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर एआईसीसी के मणिपुर प्रभारी सप्तगिरि शंकर उलाका और इबोबी सिंह की मौजूदगी में औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

भाजपा के तीन करोड़ घुसपैठियों के दावे पर चिदंबरम ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन के 'तीन करोड़ घुसपैठियों' संबंधी दावे पर सोमवार को पलटवार करते हुए उनसे पांच सवाल पूछे और जानना चाहा कि वे जिन तीन करोड़ घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, वे कौन हैं तथा क्या केंद्र एवं राज्य सरकारों ने उनकी पहचान कर ली है। मतदाता सूची से 13 करोड़ नाम हटाए जाने के विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए नवीन ने कहा था, राहुल गांधी, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गली से लेकर संसद तक हर वोट का हिसाब दे सकते हैं।

नवीन ने कहा था कि मतदाता सूची से हटाए गए नामों में ढाई करोड़ ऐसे लोगों के थे, जिनकी मौत हो चुकी है और छह करोड़ लोग ऐसे हैं, जो दूसरी जगह चले गए हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा था, तीन करोड़ घुसपैठिये हैं। लोग जानते हैं कि वे (विपक्ष) इन घुसपैठियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं।

जब तक भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल कर रहेंगे।

नवीन के बयान पर पलटवार करते हुए चिदंबरम ने उनसे पांच सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि भाजपा अध्यक्ष ने रविवार को जिन तीन करोड़ घुसपैठियों का उल्लेख किया था, वे कौन हैं और क्या केंद्र एवं राज्य सरकारों ने उनकी पहचान की है।

विपक्ष के पास अब कोई असली मुद्दा नहीं बचा: अमृता फडणवीस

मुंबई, एजेंसी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्ष के पास अब कोई असली राजनीतिक मुद्दा नहीं बचा है।श्रीमती फडणवीस ने प्रभात प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित 'भाऊ बीज' कार्यक्रम में संवाददाताओं से बात करते हुए अपने पति के खिलाफ हो रहे राजनीतिक हमलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की यह रणनीति राज्य प्रशासन के सुचारू रूप से काम करने से उपजी हताशा का नतीजा है। उन्होंने कहा, देवेंद्र जी को लगातार निशाना बनाया जाता है। लेकिन जब विपक्ष के पास उन्हें घेरने के लिए कोई असली राजनीतिक मुद्दा नहीं होता, तो वे उनकी पत्नी को निशाना बनाने लगते हैं।

उन्होंने कहा, आज विरोधियों के पास कोई सार्थक मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए उनका पूरा ध्यान उन लोगों के काम में बाधा डालने पर केंद्रित हो गया है जो कुशलता से काम कर रहे हैं।

उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे द्वारा श्री एकनाथ शिंदे और श्री आशीष शेलार पर की गई हल्की-फुल्की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर सत्ताधारी गठबंधन के भीतर किसी भी तरह के आंतरिक मतभेद की संभावना को खारिज कर दिया।

राम मंदिर चढ़ावा 'चोरी' मामला : न्यायालय ने स्वतंत्र जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई बंद की

राम मंदिर चंदा मामले की जांच वाली याचिकाओं पर सुनवाई बंद

नई दिल्ली, एजेंसी।



उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की स्वतंत्र जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को बंद कर दी और कहा कि अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ स्थानीय अदालत में मुकदमा चलेगा।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील का संज्ञान लिया कि शीर्ष अदालत की ओर से गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। उसने कहा कि अब राज्य सरकार मामले में कानून के अनुसार मुकदमा आगे बढ़ा सकती है। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना भी शामिल थे।

पीठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के एक प्रावधान का जिक्र करते हुए कहा कि चूंकि इस मामले में "जनहित का पहलू" शामिल है, इसलिए किसी अपराध के पीड़ित की तरह ही रिट याचिकाकर्ताओं को आगामी सुनवाई के दौरान अयोध्या के न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहायता करने की छूट दी जाती है। शीर्ष अदालत ने अपने समक्ष मौजूद याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पीठ ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वस्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल की है, जिसके अनुसार इस मामले में आरोपपत्र दायर कर दिया गया है। इसे देखते हुए हम रिट याचिका और इससे जुड़े अन्य मामलों का निपटारा करते हैं तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश देते हैं कि वह कानून के अनुसार इस मामले में आगे की कार्यवाही करें।

उसने कहा, चूंकि, मामले में जनहित का पहलू शामिल है, इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं को न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहायता करने की अनुमति दी जाती है। यह अनुमति उसी आधार पर दी गई है, जिस तरह कानून किसी अपराध के पीड़ित को अदालत की सहायता करने का अधिकार देता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो, इसलिए यह अदालत मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है।

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एसआईटी की जांच में पता चला है कि मंदिर में चढ़ावे का हेरफेर गिनती की प्रक्रिया के दौरान हुआ।

उन्होंने कहा कि चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया में शामिल कुछ आरोपियों ने चोरी की रकम संपत्ति में निवेश की, जबकि कुछ ने इसे बैंक में जमा करा दिया। मेहता ने कहा कि जांचकर्ता बैंकों में पैसों के लेन-देन का पता लगाने में सफल रहे हैं और संपत्ति में निवेश की बात करें तो एक मामले में सौदे से जुड़े बिक्री विलेख में 15 लाख रुपये का भुगतान दिखाया गया था, जबकि उस संपत्ति की वास्तविक कीमत 50 लाख रुपये थी। उन्होंने कहा कि बाकी रकम संभवतः नकद में चुकाई गई थी और यह चढ़ावे में हेरफेर के जरिये आई थी। मेहता ने पीठ को बताया कि एक ऑडिट भी किया गया था। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि जांच के दौरान सभी कलाकृतियां और अन्य चीजें सुरक्षित पाई गईं।

जब प्रधान न्यायाधीश ने भविष्य को लेकर चिंता जताई, तो मेहता ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं।

पंजाब के तीन आप विधायक भाजपा में, राज्य की राजनीति में हलचल

इन तीनों ने सोमवार को दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की

नई दिल्ली,एजेंसी।



पंजाब में विधान सभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को राजनीतिक झटका देते हुए उसके तीन विधायक सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। इनमें अमृतसर उत्तर से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा और समाना से विधायक एवं पूर्व मंत्री चेतन सिंह जौरामाजरा शामिल हैं।

इन तीनों ने सोमवार को दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पंजाब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पंजाब मामलों के प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया, सह-प्रभारी वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

इन तीनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी के केंद्रीय तथा प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में पंजाब को नशे, अपराध और कर्ज की समस्याओं से बाहर निकालने तथा राज्य की प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई। ढिल्लों ने कहा कि पंजाब की आप सरकार अपने वादे पूरे करने में विफल रही है, जिससे राज्य के लोग निराश है।

उन्होंने कहा कि पार्टी के तीन विधायकों का भाजपा से शामिल होना पंजाब की आप सरकार के प्रति बढ़ते असंतोष का संकेत बताया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा राज्य में लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने नशे, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थित और राज्य स्तर पर पर बढ़ते कर्ज को लेकर भगवंत मान सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आप नेतृत्व नशे के खिलाफ संघर्ष करने वालों और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशील नहीं है।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे कुंवर विजय प्रताप सिंह की आप के नेतृत्व के साथ लम्बे समय से खटपट चल रही थी। उन्होंने कहा कि आप के साथ उनकी पांच साल की 'इंटर्नशिप' अब समाप्त हो गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन के मॉडल और भाजपा नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पंजाब को शांति, उद्योग और समृद्धि के रास्ते पर लाने के लिए उनके श्री मोदी के मॉडल की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है और गैंगस्टरवाद तथा जबरन वसूली संगठित कारोबार का रूप ले चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि आप सरकार के भीतर गैंगस्टरों को संरक्षण मिल रहा है। हरमीत सिंह पठानमाजरा ने आरोप लगाया कि आप नेतृत्व ने पंजाब और प्रदेश के समुदायों से जुड़े मुद्दे उठाने वाले नेताओं को कमजोर करने का प्रयास किया। उन्होंने आप सरकार की राजकोषीय नीति की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य पर ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के बोझ तले दबा है।

उन्होंने नशे और गिरोबाज अपराधियों से मुक्त 'उभरता पंजाब' बनाने के लिए लोगों से भाजपा का समर्थन करने की अपील की। पूर्व मंत्री चेतन सिंह जौरामाजरा ने भाजपा में शामिल होने के पीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और कार्यशैली को प्रमुख वजह बताया।

उन्होंने कहा कि आप के शासन में पंजाब के गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर हो रही हैं, डिस्पेंसरियां बंद हो रही हैं और बड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य कार्ड स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफंड में देरी के कारण मंडी गोबिंदगढ़ और बटाला जैसे औद्योगिक केंद्रों को नुकसान हो रहा है। केंद्रीय मंत्रालयों के साथ राज्य सरकार समन्वय नहीं कर पा रही है जिससे राज्य को महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।

नशा तस्करी के पैसे से चल रही है आप सरकार: मजीठिया

चंडीगढ़,एजेंसी।



शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने सोमवार को आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार नशा तस्करी के पैसे से चल रही है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और मनीष सिसोदिया के करीबी बताए जा रहे नशा तस्कर को पुलिस द्वारा निर्धारित समय में आरोपपत्र दाखिल नहीं किए जाने के कारण डिफॉल्ट जमानत मिल गई।

यहां पत्रकारों से बातचीत में मजीठिया ने कहा कि लवप्रीत सिंह आप का कार्यकर्ता होने के साथ-साथ 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान में पदाधिकारी भी था। उनके अनुसार, लवप्रीत को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से कथित तौर पर आठ किलो हेरोइन बरामद हुई थी,जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 80 करोड़ रुपये बताई गई थी।

मजीठिया ने आरोप लगाया कि बाद में बरामदगी की मात्रा घटाकर 4.5 किलो कर दी गई और उसे जेल से बाहर निकालने के प्रयास शुरू हो गए। अकाली नेता ने दावा किया कि लवप्रीत को गिरफ्तार करने वाले थाना प्रभारी का पहले तबादला किया गया और फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले में आरोपपत्र दाखिल करने में देरी की। उन्होंने कहा कि 180 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने से तीन दिन पहले पंजाब पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।

मजीठिया के मुताबिक, उन तीन दिनों में अवकाश होने के कारण अदालत से विस्तार नहीं मिल सका और लवप्रीत को डिफॉल्ट जमानत मिल गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि अदालत में अभियोजन पक्ष ने देरी का कारण फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट लंबित होना बताया। मजीठिया ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि एफएसएल भी गृह मंत्री के अधीन है।

मजीठिया ने आरोप लगाया कि राज्य में इसी तरह नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों को कमजोर किया जा रहा है और इसके बदले आप नेतृत्व तक करोड़ों रुपये पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इसी कारण पंजाब में नशे का कारोबार बढ़ रहा है। हालांकि, ये सभी आरोप उन्होंने राजनीतिक बयान के तौर पर लगाए। अकाली नेता ने यह भी आरोप लगाया कि लवप्रीत की संपत्तियां अब तक जब्त नहीं की गईं, जबकि विपक्षी नेताओं के खिलाफ पुलिस नशीले पदार्थों के मामले दर्ज कर रही है।

सार समाचार

तीन विधायकों के जाने से आप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा: नील गर्ग

चंडीगढ़,एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब प्रवक्ता नील गर्ग ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे आप की चिंता करने के बजाय पंजाब में अपने घटते जनाधार और लोगों के बीच विश्वसनीयता पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा, उसके मुद्दे और पंजाब का विकास 'आप' की सबसे बड़ी ताकत हैं तथा कुछ विधायकों के पार्टी छोड़ने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा नेताओं के उन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कि तीन विधायकों के पार्टी छोड़ने से आप का संगठन बिखर रहा है, श्री गर्ग ने कहा कि पार्टी इन विधायकों से काफी पहले ही दूरी बना चुकी थी। उन्होंने कहा कि विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह को जून 2025 में ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। अन्य विधायकों के राजनीतिक फैसले उनका अपना मामला हैं। गर्ग ने कहा कि लोकतंत्र में किसी पार्टी का भविष्य जनता तय करती है।

धर्मशाला में दिवाली पर 'ग्रीन पटाखों' की बिक्री की अनुमति

धर्मशाला,एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दिवाली के अवसर पर केवल स्वीकृत 'ग्रीन पटाखों' की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी गयी है। राज्य में दिवाली त्योहार को देखते हुए उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) मोहित रतन ने धर्मशाला उप-मंडल में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए केवल स्वीकृत 'ग्रीन पटाखों' की ही अनुमति दी गयी है। एसडीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए लाइसेंस प्राप्त और अधिकृत विक्रेताओं द्वारा पटाखे बेचने के लिए चार जगहें तय की हैं।

छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों से 23 जनवरी के बाद हटेगा अतिक्रमण

रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्तियों पर अवैध कब्जे और कथित फर्जी रजिस्ट्रियों के मामलों में कार्रवाई तेज करने की तैयारी की है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा है कि 23 जनवरी के बाद वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

इसके साथ ही कथित फर्जी तरीके से कराई गई रजिस्ट्रियों को शून्य कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी।डॉ. सलीम राज ने आज बताया कि राज्य में वक्फ संपत्तियों से जुड़े विभिन्न मामलों में अब तक 418 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें संपत्तियों की कथित फर्जी रजिस्ट्री कराने से संबंधित मामले भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संबंधित रजिस्ट्रारों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड की ओर से 23 जनवरी के आसपास ऐसी रजिस्ट्रियों को शून्य कराने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है।

अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे राहुल गांधी: मेघवाल

जबलपुर, एजेंसी।



केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी लोकतांत्रिक संस्थाओं को धमकाकर देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अपनी साख खो चुके हैं, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने और अराजकता फैलाने वालों को सबक सिखाने के लिए जनता आगे आए।

केन्द्रीय मंत्री मेघवाल सोमवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' संकल्प पदयात्रा को संबोधित कर रहे थे। जबलपुर के शहीद स्मारक गोल बाजार में आयोजित ढाई किमी से अधिक लंबी इस पदयात्रा में एक लाख से अधिक से अधिक लोग उमड़े। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने भी पदयात्रा में सहभागिता कर जनसैलाब को संबोधित किया।

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि पदयात्रा में जिस उत्साह और बड़ी संख्या में जनता की सहभागिता देखने को मिली है, वह इस बात का प्रमाण है कि देश की जनता लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि 06 अक्टूबर को राहुल गांधी और उनके कुछ विपक्षी दलों के सांसद चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते थे। चुनाव आयोग ने उनसे पूछा कि आप कितने लोग मिलना चाहते हैं और आपका ज्ञापन क्या है? आप प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम दे दीजिए, आपसे मुलाकात की जाएगी। लेकिन उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम नहीं दिए और इसके बाद अराजकता फैलाने के लिए सड़क पर उतर गए। आपने वह पूरा दृश्य देखा होगा कि किस तरह धक्का-मुक्की हुई। यह सब अराजकता का ही उदाहरण है।

मेघवाल ने कहा कि विपक्षी दलों के 10 लोग राष्ट्रपति जी से मिले। राष्ट्रपति जी ने उनसे कहा कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, उसके प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। लेकिन वे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी को सामने आकर इस विषय पर अपनी बात रखनी पड़ी। 11 अक्टूबर की रात और 12 अक्टूबर 2026 को उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति याचिका के माध्यम से अपनी बात रख सकता है। हम याचिकाओं को सुनते हैं। यदि आपको याचिका लगानी है तो लगाइए, हम सुनेंगे। लेकिन इस तरह कुछ करने और धमकाने वाली भाषा का हम समर्थन नहीं करते।

विवादित वीडियो पोस्ट पर अमित जोगी ने मांगी माफी

रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता अमित जोगी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सोशल मीडिया पर आज साझा किए गए एक व्यंग्यात्मक वीडियो पर विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो की आलोचना और सोशल मीडिया पर उठे सवालों के बाद अमित जोगी ने संबंधित पोस्ट हटा दी और लोगों की भावनाएंआहत होने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। जानकारी के अनुसार, अमित जोगी ने कथित वोट चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाते हुए एक वीडियो साझा किया था। वीडियो में दोनों के मुखौटे पहने दो व्यक्तियों को दिखाया गया था। इसमें प्रतीकात्मक रूप से दोनों की शादी कराई गई थी और इसके बाद हनीमून से संबंधित दृश्य प्रस्तुत किए गए थे। वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद इसकी विषयवस्तु और प्रस्तुति को लेकर आलोचनाएं शुरू हो गईं।

भारत की बागडोर अमृत पीढ़ी के हाथों में : मांडविया



जगदलपुर, एजेंसी।

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख एल. मांडविया ने सोमवार को कहा कि देश भर में एक लाख युवा लीडर्स तैयार करने का लक्ष्य है ताकि वे सीधे नीति-निर्माण और जनसेवा से जुड़ सकें।

केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया आज कृषि महाविद्यालय कुम्हरावण्ड के सभागार में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं के साथ सीधा और आत्मीय संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह मंच देश के युवाओं को नवाचार, मेंटरशिप, वॉलंटियरिंग और करियर के नए अवसरों से जोड़ने के लिए तैयार किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने लोकतंत्र और समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर प्रांजल नाम के एक छात्र से सीधी बात की और पारदर्शी एवं शुद्ध मतदाता सूची के महत्व को समझाया।

उन्होंने रेखांकित किया कि देश के सही नेतृत्व और सशक्त लोकतंत्र की नींव प्रत्येक युवा के निष्पक्ष वोट की ताकत पर टिकी होती है। उन्होंने युवाओं के सपनों और करियर का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

विदेशी ताकतों के इशारे पर देश में भ्रम फैलाने का हो रहा प्रयास: अन्नपूर्णा देवी

गिरिडीह, एजेंसी।



केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को टैक्स, स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी, कथित भ्रष्टाचार, अवैध खनन और राज्य की कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा।श्रीमती देवा ने कहा कि राज्य सरकार ने टैक्स और स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी कर आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है। उनके अनुसार, राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसका असर विकास कार्यों पर भी पड़ रहा है।

खनन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में खनन गतिविधियों पर रोक के बावजूद अवैध खनन जारी है। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले में कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है और सरकारी संरक्षण में उनकी जेबें भरी जा रही हैं।

केंद्रीय मंत्री श्रीमती देवी ने सोमवार को गिरिडीह में आयोजित प्रेसवार्ता कर बताया कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारे पर देश में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की जनता उनकी काबिलियत से भली-भांति परिचित है।

उन्हें यह तक समझ नहीं है कि देश के सामने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मॉक पार्लियामेंट तक ही ठीक हैं।श्रीमती देवी ने कहा कि राहुल गांधी की भाषा और बयानबाजी उनकी अपनी नहीं लगती, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी विदेशी रिमोट से संचालित हो रहे हैं।

उमर को सिविल सचिवालय में 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया

जम्मू,एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सोमवार को सिविल सचिवालय में 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया।वार्षिक 'दरबार मूव' (राजधानी बदलने की प्रक्रिया) के तहत सरकारी कार्यालयों ने यहां अपना कामकाज शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री का सिविल सचिवालय पहुंचने पर उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने स्वागत किया। इसके बाद उन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक टुकड़ी द्वारा 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया।प्रशासनिक कामकाज के श्रीनगर से शीतकालीन राजधानी (जम्मू) में स्थानांतरित होने के साथ ही 2026-27 के छह महीने के शीतकालीन सत्र के लिए 100 से अधिक सरकारी कार्यालयों ने यहां अपना काम फिर से शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने दरबार मूव के बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों और प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठकें भी कीं।

फरक्का जल संधि बिहार के हित में नहीं: संजय झा

लखीसराय, एजेंसी।



जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने सोमवार को कहा कि वर्ष 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई फरक्का जल संधि बिहार के हित में नहीं है और इसका भविष्य में नवीनीकरण नहीं होना चाहिए। झा ने कहा कि भविष्य में यदि इस संबंध में कोई नई संधि होती है तो उसमें वर्ष 2050 तक बिहार की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

झा ने आज लखीसराय में जदयू के 'फरक्का जल संधि पर नीतीश संवाद' कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ करते हुए कहा कि फरक्का जल संधि के कारण बिहार का जल प्रबंधन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और राज्य के लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। शुष्क मौसम में गंगा के साथ-साथ बिहार की आंतरिक नदियों से भी पानी खींचकर बांग्लादेश को दिया जाता है। इससे किसानों की सिंचाई, लोगों के पेयजल, उद्योगों की जरूरतों और लाखों लोगों की आजीविका पर असर पड़ रहा है।

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बिहार और केंद्र की तत्कालीन सरकारों ने इस संधि के दौरान राज्य के हितों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि संधि करते समय बिहार के किसानों, आम लोगों और युवाओं के भविष्य का ध्यान नहीं रखा गया। बिहार की जल आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर लिया गया फैसला राज्य के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है।

झा ने कहा कि गंगा बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार से निकलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जदयू ने इस जनजागरूकता अभियान की शुरुआत पांच सितंबर को बक्सर से की थी। अभियान का समापन चार नवंबर को कटिहार में होगा। पहले चरण में बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय और खगड़िया तथा दूसरे चरण में सारण, वैशाली, समस्तीपुर और पटना में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। तीसरे चरण की शुरुआत लखीसराय से हुई है। इसके बाद मुंगेर, भागलपुर और कटिहार में कार्यक्रम होंगे।

इस अवसर पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि फरक्का बराज और फरक्का जल संधि से बिहार को दोहरा नुकसान हो रहा है। उनके अनुसार, फरक्का बराज के कारण गंगा में गाद जमा होने से नदी का तल ऊंचा हो गया है, जिससे हर साल बाढ़ की समस्या पैदा होती है। वहीं, जल संधि के कारण बिहार को अपने हिस्से का पानी भी बांग्लादेश को देना पड़ता है, जिससे राज्य के कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संधि का बोझ अकेले बिहार को उठाना पड़ रहा है।कुशवाहा ने संसद में इस मुद्दे को उठाने और इसे राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाने के लिए श्री झा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि फरक्का जल संधि पर पुनर्विचार के साथ बिहार के हितों और जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

कार्यक्रम में विधायक रामानंद मंडल और जदयू जिलाध्यक्ष रामानुज शर्मा ने कहा कि पार्टी का यह अभियान किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि बिहार के हक और जनसरोकार से जुड़ा है। इसके माध्यम से लोगों को फरक्का जल संधि के संभावित प्रभावों की जानकारी दी जा रही है और बिहार की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

शिल्पग्राम में रायपुर की आस्था भट्ट भजन गायन, दुर्ग की आरती बारले पंथी नृत्य और कबीरधाम के राकेश सेन लोकमंच की प्रस्तुति देंगे

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का समापन आज, शाह करेंगे समारोह में शिरकत

रायपुर, एजेंसी।



छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय राज्योत्सव 2026 का समापन मंगलवार, तीन नवंबर को नवा रायपुर अटल नगर स्थित राज्योत्सव मैदान में होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रदेश की प्रतिभाओं को राज्य अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राज्योत्सव के अंतिम दिन राज्य अलंकरण समारोह के साथ लोककला, शास्त्रीय नृत्य और संगीत की विविध प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। मुख्य मंच पर शाम छह बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे।

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के कलाकार शाम छह से साढ़े छह बजे तक लोकसंगीत प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद शाम साढ़े छह से सात बजे तक पद्मश्री उषा बारले अपनी प्रस्तुति देंगी।

मुख्य मंच पर शाम सात बजे से रात नौ बजे तक राज्य अलंकरण समारोह आयोजित होगा। इसमें कला, संस्कृति, साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। समारोह के बाद रात नौ बजे से बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक अभिजीत भट्टाचार्य अपने लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देंगे।राज्योत्सव के अंतिम दिन शिल्पग्राम में भी सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होंगी। दोपहर तीन बजे से शुरू होने वाले कार्यक्रमों में प्रदेश के विभिन्न जिलों के कलाकार कुल दस प्रस्तुतियां देंगे। इनमें पंथी नृत्य, आदिवासी लोकसंगीत, कथक, भजन, सूफी संगीत, लोकमंच और नाट्य विधाएं शामिल हैं।

शिल्पग्राम में रायपुर की आस्था भट्ट भजन गायन, दुर्ग की आरती बारले पंथी नृत्य और कबीरधाम के राकेश सेन लोकमंच की प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा रायपुर के दिनेश कुमार जांगड़े पंथी नृत्य तथा पूर्णिमा साहू जसगीत एवं जगराता भजनों की प्रस्तुति देंगी।इसी क्रम में अभिषेक सोनकर आदिवासी लोकसंगीत एवं नृत्य, दीपाली पाण्डेय कथक समूह नृत्य और अनुष्णा रॉय चौधरी कथक की प्रस्तुति देंगी। वृद्धुमन वचस्पति भारती सूफी संगीत तथा आनंदकुमार पाण्डेय नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि राज्योत्सव के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोककला, सांस्कृतिक परंपराओं और जनजातीय विरासत को व्यापक मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोजन में राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकारों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिससे प्रदेश की पारंपरिक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पंडवानी, पंथी, सुआ, करमा और आदिवासी नृत्य जैसी विधाएं प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : अरुण साव

रायपुर, एजेंसी।



उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने सोमवार को मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने निर्माणाधीन प्रवेश द्वार, स्विमिंग पूल, नालंदा परिसर और नगर पालिका भवन का निरीक्षण कर अधिकारियों से कार्यों की प्रगति और वर्तमान स्थिति की जानकारी ली।

अरुण साव ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे हों और निर्माण में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए। साव के साथ विधायक धरमलाल कौशिक भी निरीक्षण के दौरान मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री साव ने सबसे पहले साइंस कॉलेज के पास नवागढ़ रोड पर निर्माणाधीन प्रवेश द्वार का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने स्विमिंग पूल और नालंदा परिसर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने दोनों निर्माणाधीन परिसरों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा।

वनडे सीरीज में इन पांच खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी निगाहें

विराट और रोहित के प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें रहेंगी। डेरिल मिचेल बन सकते हैं बड़ा खतरा।

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आगाज बुधवार (4 नवंबर) से होगा। टी20 सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम वनडे में भी दमदार प्रदर्शन करना चाहेगी। वहीं, न्यूजीलैंड आखिरी दो टी20 मैचों की अपनी फॉर्म को एकदिवसीय सीरीज में भी बरकरार रखना चाहेगी। आइए आपको ऐसे पांच खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, जिनके प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें रहने वाली हैं। विराट कोहलीः टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का यह न्यूजीलैंड का आखिरी दौरा माना जा रहा है।

ऐसे में इस सीरीज में कोहली के प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें रहेंगी। विराट को न्यूजीलैंड में खेलना काफी रास आता है। उन्होंने यहां खेले 11 वनडे मैचों में 46 की औसत से 514 रन बनाए हैं।



न्यूजीलैंड की सरजमीं पर कोहली एक शतक और 4 अर्धशतक लगा चुके हैं।

रोहित शर्माः कोहली के साथ-साथ रोहित के लिए भी यह न्यूजीलैंड का आखिरी दौरा होगा। अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज रोहित के लिए काफी अहम मानी जा रही है। तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों में रोहित के ऊपर टीम को वनडे सीरीज में शानदार शुरुआत देने का दारोमदार होगा।

ग्लेन फिलिप्सः टी20 सीरीज में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से रिकॉर्ड्स की भरमार लगाने वाले ग्लेन फिलिप्स वनडे में भी टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। 5 मैचों की टी20 सीरीज में फिलिप्स ने कुल 341 रन बनाए और इस दौरान 3 अर्धशतक और एक शतक भी लगाया। फिलिप्स की बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ-साथ पारी को बुनने और स्कोरबोर्ड को चलाने की काबिलियत भी नजर आई है।

मोहम्मद सिराजः न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मोहम्मद सिराज के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। सिराज को इस साल सिर्फ 4 वनडे मैच खेलने का मौका मिला है और इस दौरान उन्होंने सिर्फ 4 विकेट चटकाए हैं। सिराज का साल 2026 में बॉलिंग औसत 44 का रहा है। हालांकि, न्यूजीलैंड ए के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट में सिराज अच्छी लय में दिखाई दिए हैं।

डेरिल मिचेलः भारत के खिलाफ डेरिल मिचेल का रिकॉर्ड दमदार रहा है। मिचेल को भारत के खिलाफ खेलना काफी रास आता है। उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ अब तक खेले 16 वनडे मुकाबलों में 72 की औसत से खेलते हुए 938 रन बनाए हैं। इस दौरान वह 4 शतक और 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। साल 2026 में भी डेरिल मिचेल बेहतरीन फॉर्म में नजर आए हैं और वह 6 मुकाबलों में 94 की औसत से 473 रन बना चुके हैं।

रविंद्र और चैपमैन भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर

ऑकलैंड, एजेंसी। न्यूजीलैंड को लगा दोहरा झटका, चोटिल मार्क चैपमैन और रचिन रविंद्र भारत के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चैपमैन और रविंद्र को अपनी-अपनी चोटों से उबरने के लिए और समय चाहिए। एमआरआई स्कैन से पता चला है कि चैपमैन की बायीं हैमस्ट्रिंग को रिहैब के लिए और दो सप्ताह चाहिए, जबकि रविंद्र के दाहिने कंधे को पूरी क्षमता से क्षेत्ररक्षण करने के लायक होने से पहले और समय की जरूरत है।

न्यूजीलैंड ने अब मूल रूप से आखिरी दो वनडे मैचों का हिस्सा होने वाले टिम साइफर्ट को पूरी सीरीज के लिए शामिल कर लिया है।

जबकि इस महीने 35 साल के होने वाले हेनरी निकल्स को पहले तीन मैचों के लिए टीम में लाया गया है। फिलहाल न्यूजीलैंड ए और इंडिया ए के बीच चल रही रेड-बॉल सीरीज़ में खेल रहे डीन फ़ॉक्सक्रॉफ़्ट को आख़िरी दो मैचों के लिए वनडे टीम में चुना गया है। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने कहा, ₹हर



कोई जानता है कि मार्क और रचिन इस टीम के लिए कितने अहम हैं, इसलिए यह अफसोस की बात है कि उन्हें इस सीरीज़ से बाहर रहना पड़ रहा है।

मैंने पिछले सप्ताह मार्क से मुलाकात की थी और हालांकि वे निराश हैं, लेकिन वे मैदान पर वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रचिन की बात करें तो, उनका कंधा अभी तक उस स्थिति में नहीं आ पाया है जहां वह सफेद गेंद क्रिकेट में आसानी से क्षेत्ररक्षण कर सकें, इसलिए इस महीने के अंत में होने वाली टेस्ट सीरीज को देखते हुए हम कोई बेवजह का जोखिम नहीं लेना चाहते।

सितंबर में, एक प्रोमो शूट के दौरान रविंद्र के कंधे में चोट लग गई थी, जबकि यूरोपियन टी-20 प्रीमियर लीग के दौरान चैपमैन की हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था। निकल्स की वापसी बिल्कुल सही समय पर हुई है क्योंकि उन्होंने शनिवार को फ़ोर्ड ट्रॉफ़ी में कैंटरबरी के लिए ओपनिंग करते हुए 119 रन बनाए थे। उन्होंने 92 वनडे मैच खेले हैं, और वह जुलाई में न्यूजीलैंड के वेस्टइंडीज दौरे का भी हिस्सा थे।

भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के बीच में ही बाहर होने वाले मैट हेनरी सोमवार को वनडे स्क्वॉड में शामिल हो गए हैं और उनके खेलने की फिटनेस का भी आकलन किया जाएगा। मैथ्यू फिशर जिन्हें मूल रूप से केवल आख़िरी दो मैचों के लिए चुना गया था, उन्हें एक अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प के रूप में पूरी सीरीज के लिए शामिल कर लिया गया है। पहला वनडे बुधवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। भारत के खिलाफ न्यूज़ीलैंड का अपडेटेड वनडे टीम इस प्रकार हैः

पाटीदार का नाबाद शतक, दिल्ली ने सर्विसेज 266 पर समेटा

नई दिल्ली,एजेंसी। अमन चौधरी (चार विकेट) और नवदीप सैनी (तीन विकेट) के बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत दिल्ली ने सोमवार को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप सी मुकाबले के पहले दिन का खेल समाप्त होने के समय तक सर्विसेज की पारी को समेट दिया। इस दौरान कप्तान रजत पाटीदार ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए सर्विसेज की ओर (नाबाद 111) रनों की शतकीय पारी खेलकर अपनी टीम को 266 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया।

आज यहां सर्विसेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। नवदीप सैनी ने पहले ही ओवर में शुभम रोहिल्ला को बिना खाता खोले ही अपना शिकार बना लिया। इसके बाद सर्विसेज ने 44 रन के स्कोर तक अपने तीन और विकेट गंवा दिये। ऐसे संकट के समय मोहित अहलावत ने रजत पाटीदार के साथ पांचवें विकेट के लिए 69 रन जोड़े। 36वें ओवर में अमन चौधरी ने मोहित अहलावत (33) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद दिल्ली की गेंदबाजी के आगे पाटीदार को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज अधिक देर तक नहीं टिक सका। पाटीदार ने 196 गेंदों में 10 चौके लगाते हुए (नाबाद 111) रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली।

पुलकित नारंग (30), जयंत गोएत (17), नकुल शर्मा (12) और अर्जुन शर्मा (12) रन बनाकर आउट हुये।

निचले क्रम के बल्लेबाजों के दम पर न्यूजीलैंड ए ने बनाई बढ़त

मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार ने गेंदबाजी में किया शानदार प्रदर्शन।

क्राइस्टचर्च,एजेंसी। मोहम्मद सिराज (चार विकेट) और मुकेश कुमार(पांच विकेट) के बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद निचले क्रम के बल्लेबाजों की बदौलत न्यूजीलैंड ए ने दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच में इंडिया ए के खिलाफ 78 रनों की बढ़त हासिल कर ली। स्टंप्स के समय इंडिया ए ने बिना कोई विकेट खोए दूसरी पारी में 32 रन बना लिये है। 208 रनों की जो साझेदारी कल से चल रही थी, वह आज के दिन के दूसरे ओवर में ही टूट गई।



सिरीज ने मैथ्यू बॉयल (110) रन को आउट कर इंडिया ए को चौथी सफलता दिलाई। इंडिया ए ने पहले सेशन में सिर्फ 73 रन देकर चार विकेट झटके, जिससे लंच के समय न्यूजीलैंड ए का स्कोर सात विकेट पर 291 रन हो गया। ऐसा लग रहा था कि इंडिया ए को थोड़ी बढ़त मिल जाएगी, लेकिन न्यूजीलैंड ए के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने डटकर मुकाबला किया।

आखिरी तीन विकेटों के लिए हुई साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजों को मैदान पर 43 ओवर और बिताने पर मजबूर कर दिया। आखिरी विकेट के लिए हुई साझेदारी लगभग 25 ओवर तक चली, जिसने अब तक भारतीय तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन का असर कम कर दिया और न्यूजीलैंड ए को पहली पारी में 78 रनों की बढ़त दिला दी।

इसके बाद, इंडिया ए के ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और बी साई सुदर्शन ने बिना किसी बड़ी परेशानी के दिन के खेल खत्म होने से पहले के 11 ओवर निकाल दिए। इस दौरे पर अपनी पिछली तीन पारियों में 17, 5 और शून्य बनाने वाले जायसवाल इस बार काफी आत्मविश्वास में दिखे और उन्होंने अपनी पारी के दौरान तीन चौके लगाए। साई सुदर्शन और जायसवाल दोनों ने नई गेंद से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों की थोड़ी-बहुत मूवमेंट को अच्छे से संभाला और काफी सतर्क रहे। दिन की आखिरी गेंद पर एक डरावना पल भी आया, जब जायसवाल तेज गेंदबाज ब्रेट रैंडेल की एक गेंद पर आगे बढ़कर खेलने गए। वह पूरी तरह से फंस गए और गेंद उनके बल्ले के बाहरी किनारे के काफी करीब से निकल गई। हालांकि, अंपायर ने न्यूजीलैंड ए की अपील को नहीं माना।

इससे पहले, मोहम्मद सिराज ने आज की अपनी पहली ही गेंद पर मैथ्यू बॉयल को स्लिप में कैच आउट करा दिया। बॉयल 110 रन बनाकर आउट हुए। स्लिप में तैनात अकेले फील्डर देवदत्त पडिक्कल ने अपनी बाईं ओर छलांग लगाई और एक हाथ से ऐसा कैच पकड़ा जो लगभग उनके पीछे था। इस कैच के साथ ही एक बड़ी साझेदारी का अंत हो गया।

सेंथिलकुमार ने फाइनल में बनाई जगह

ब्रनो,एजेंसी। भारत के वेलावन सेंथिलकुमार ने ब्रनो में चल रहे चेक ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। 35,000 अमेरिकी डॉलर इनामी राशि वाले इस पीएसए कॉपर-लेवल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में उन्होंने फ्रांस के खिलाड़ी और विश्व नंबर 32 ऑगस्ट डुसॉर्ड को हराया। सेंथिलकुमार ने सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाड़ी को 11-7, 12-10, 11-1 से मात दी। चौथे वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी अब फाइनल में स्कॉटलैंड के ग्रेग लोबन (जो शीर्ष वरीयता प्राप्त हैं और विश्व रैंकिंग में 31वें नंबर पर हैं) का सामना करेंगे। सेंथिलकुमार इस सीजन में अपना दूसरा खिताब जीतने की कोशिश करेंगे।

शीर्ष वरीयता प्राप्त लोबन ने फ्रांस के तौफिक मेखल्फी को 11-9, 11-5, 11-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले, सेंथिलकुमार ने अर्जेंटीना के जेरेमियास अजाना को 11-3, 11-8, 11-7 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। पहले गेम में भारतीय खिलाड़ी ने अर्जेंटीना के जेरेमियास अजाना को आसानी से 11-3 से हराया। इसके बाद, रैलियां तेज, कड़ी और रोमांचक हो गई थीं। सेंथिलकुमार ने कोर्ट के अगले हिस्से में बेहतरीन खेल दिखाते हुए बाकी गेम 11-8 और 11-7 से अपने नाम किया था।

भारतीय खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के विश्व नंबर 64 और आठवें वरीयता प्राप्त जेरेमियास अजाना को 11-3, 11-8, 11-7 से हराया था। इससे पहले, टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में उन्हें 'बाय' (सीधे अगले दौर में प्रवेश) मिला था, और दूसरे दौर में उन्होंने ब्राजील के डिएगो गोब्बी को 11-4, 11-7, 11-2 से मात दी थी।

बिजनेस

गुजरात में 9.08 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगे

गांधीनगर। केंद्र सरकार की 'पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना' के तहत गुजरात में 9.08 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। इसके साथ ही, मार्च 2027 तक 10 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाने के लक्ष्य का 90 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया गया है। इन सोलर सिस्टमों की कुल क्षमता 3,408 मेगावाट है।

दिवाली से पहले कीमती धातुओं में लौटी तेजी

नई दिल्ली, एजेंसी। कई दिनों से लगातार गिरावट की मार झेल रहे सोने और चांदी के भाव में सप्ताह की शुरुआत के साथ तेजी लौटती दिखाई दी। धनतेरस और दिवाली से ठीक पहले कीमती धातुओं में आई इस रिकवरी ने ज्वेलरी खरीदारों और निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते से व्यापार और निवेश के खुलेंगे नए अवसर

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत और न्यूजीलैंड द्विपक्षीय संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों देश पारंपरिक कूटनीतिक मित्रता से आगे बढ़कर व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, कृषि और रणनीतिक सहयोग पर आधारित व्यापक साझेदारी की ओर जा रहे हैं। यह जानकारी एक लेख में दी गई। ग्रीक समाचार पोर्टल डायरेक्टस में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इससे दोनों देशों के कारोबारियों, किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), उद्यमियों और युवा पेशेवरों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। लेख में कहा गया है कि इस समझौते का महत्व केवल सीमा शुल्क में कटौती तक सीमित नहीं है। यह बाजार तक पहुंच बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, निवेश



को बढ़ावा देने, कौशल एवं प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने और एक-दूसरे की पूरक क्षमताओं वाली दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच मजबूत कारोबारी संबंध बनाने का ढांचा प्रदान करता है।

'रोडमैप टू 2030' से मजबूत हुई व्यापक रणनीतिक साझेदारी इस आर्थिक जुड़ाव को दीर्घकालिक दिशा प्रदान करती है। एफटीए और इसके साथ जुड़ी सहयोग पहल मिलकर भारत और न्यूजीलैंड को अधिक विविधतापूर्ण, मजबूत और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने में मदद कर सकती हैं। इस एफटीए की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक न्यूजीलैंड की ओर से भारत के सभी 8,284 उत्पाद श्रेणियों के निर्यात पर तत्काल शून्य शुल्क की सुविधा देना है। इससे भारतीय निर्यातकों को कीमतों के मामले में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने, विदेशी बाजारों में विविधता लाने और विकसित अर्थव्यवस्था में अपनी मौजूदगी मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। श्रम-प्रधान और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को इस समझौते से विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान, मशीनरी, रत्न एवं आभूषण, खेल के सामान, जूते और चमड़े के उत्पाद उन क्षेत्रों में शामिल हैं, जिनमें निर्यात की काफी संभावनाएं हैं। ये उद्योग बेहतर बाजार पहुंच का लाभ उठाकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं, नए ऑर्डर हासिल कर सकते हैं और अपने वितरण नेटवर्क को मजबूत कर सकते हैं।

इस समझौते से एमएसएमई, कारीगरों और महिला उद्यमियों को भी बाजार के बढ़ते अवसरों का लाभ मिलने की उम्मीद है। छोटे कारोबारियों को अक्सर अधिक लेनदेन लागत, बाजार से जुड़ी सीमित जानकारी और विदेशों में कारोबारी संबंध स्थापित करने में कठिनाइयों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में परेशानी होती है।

बेहतर शुल्क सुविधा, संस्थागत सहयोग और कारोबारियों के बीच मजबूत संपर्क से इन बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। लेख में आगे कहा गया है कि एफटीए के रणनीतिक ढांचे के तहत 2030 तक वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर लगभग 3 अरब डॉलर तक पहुंचने की परिकल्पना की गई है। ये लक्ष्य दोनों देशों की महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं, लेकिन इन्हें हासिल करना प्रभावी क्रियान्वयन, कारोबारियों की भागीदारी और कई क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि पर निर्भर करेगा।

दीपावली से पहले भारतीय शेयर बाजार ने भरा दम

मुंबई,एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 1,233.25 अंक या 1.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 75,692.78 और निफ्टी 387.70 अंक या 1.68 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,440.80 पर बंद हुआ।

बाजार की तेजी को सहारा कमोडिटीज और एनर्जी स्टॉक्स से मिला। सूचकांकों में निफ्टी ऑयलएंडगैस 5.95 प्रतिशत और निफ्टी कमोडिटीज 4.01 प्रतिशत की तेजी के साथ टॉप गेनर्स थे। इसके अलावा, निफ्टी एनर्जी 3.92 प्रतिशत, निफ्टी इन्फ्रा 3.70 प्रतिशत, निफ्टी मेटल 3.21 प्रतिशत, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2.70 प्रतिशत, निफ्टी पीएसई 2.34 प्रतिशत, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 2.23 प्रतिशत और निफ्टी इंडिया डिफेंस 1.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे अधिक तेजी दिखाने वाले सूचकांक थे।



दूसरी तरफ, निफ्टी मीडिया -0.76 प्रतिशत, निफ्टी आईटी -0.50 प्रतिशत, निफ्टी प्राइवेट बैंक -0.14 प्रतिशत और निफ्टी फार्मा -0.07 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुए।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप भी बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 682.15 अंक या 1.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 57,983.40 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 131.70 अंक या 0.71 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई, एनटीपीसी, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, बीईएल, एचयूएल, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, इंटरग्लोब एविएशन, एचडीएफसी बैंक, एमएंडएम, ट्रेंट, भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, टाइटन, अदाणी पोर्ट्स, इटरनल, आईटीसी और एचसीएल टेक गेनर्स थे। इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा और टीसीएस लूजर्स थे।

जानकारों ने कहा कि भारतीय शेयर बाजारों ने सप्ताह की मजबूत शुरुआत की। इसके पीछे मुख्य कारण उम्मीद से बेहतर दूसरी तिमाही के नतीजे और घरेलू स्तर पर सकारात्मक संकेत रहे। अक्टूबर में यात्री वाहनों की बिक्री में वृद्धि ने त्योहारी सीजन की अच्छी मांग को दर्शाया, जिससे बाजार का उत्साह और बढ़ा।

नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी एसएईएल ने शुरू की धान की पराली की खरीद

नई दिल्ली,एजेंसी। नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी एसएईएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एसएईएल) ने कृषि अपशिष्ट को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाले अपनी विद्युत इकाइयों के लिए इस साल

धान कटाई सत्र में लगभग 20 लाख टन धान की पराली की खरीद का अपना एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया कि पराली की खरीद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों से की जा रही है।

कंपनी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह पराली कृषि के कूड़े करकट से बिजली उत्पादन करने वाले 11 ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाएगा। इन संयंत्रों की कुल क्षमता 164.9 मेगावाट है। कंपनी का कहना है कि उसके इन



प्रयासों से वह देश को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने के प्रयास में मदद के साथ साथ खेतों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को घटाने में योगदान दे रही है। इससे किसानों की आय भी बढ़ती है।

एसएईएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कार्यकारी निदेशक लक्षित अवला ने कहा, ₹ भारत अब धान की पराली और अन्य फसल अवशेषों को केवल एक मौसमी वेस्ट मैनेजमेंट समस्या के रूप में देखने के नजरिए से आगे बढ़ने लगा है। हम किसान समुदायों को पराली प्रबंधन के बेहतर तरीके अपनाने और इससे असली आर्थिक फायदा उठाने में मदद जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में हमारे एग्री वेस्ट-टु-एनर्जी प्लांट्स अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर डाल रहे हैं।

ये कचरे से कमाई के नए स्रोत बनाकर और ईंधन की लागत घटाकर लाभ पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा, ये परियोजनाएं कचरा इकट्ठा करने, प्रोसेसिंग और प्लांट चलाने में रोजगार के अवसर पैदा करके स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं। विज्ञप्ति में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों को धान की पराली जलाने की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने के उद्देश्य से कार्य योजनाओं को लागू करने के वर्ष 2026 में जारी निर्देशों का उल्लेख किया गया है।

विदेशी ऑर्डर के दम पर अक्टूबर में विनिर्माण क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन

मुंबई, एजेंसी। विदेशों से मिले नये ऑर्डर बढ़ने से घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में तेजी का क्रम अक्टूबर में भी जारी रहा हालांकि सितंबर की तुलना में इसकी रफ्तार कुछ कम हुई है।उत्पादन, ऑर्डर और मुद्रास्फीति जैसे मानकों पर माह-दर-माह गतिविधियों को मापने वाला एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अक्टूबर में 54.7 रहा। सूचकांक का 50 से ऊपर रहना वृद्धि को दिखाता है। सितंबर में यह 55.1 रहा था।

भारत में एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा कि सितंबर की तुलना में कम रहने के बावजूद अक्टूबर में विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार हुआ है। सूचकांक अपने दीर्घावधि औसत से ऊपर रहा



है। उन्होंने कहा, मजबूत अंतरराष्ट्रीय मांग से निर्यात के नये ऑर्डर छह महीने के उच्चतम स्तर पर रहे। इससे उत्पादन में मजबूत वृद्धि देखी गई।

उत्पादकों ने उथल-पुथल भरे वैश्विक माहौल में कच्चे माल के भंडार में भी आठ महीने की सबसे तेज बढ़ोतरी की ताकि आने वाले समय में इसकी कमी की आशंका न रहे। भंडारी ने बताया कि कुछ कच्चे माल और ऊर्जा की लागत में तेजी देखी गई, लेकिन कुल मिलाकर लागत और उत्पादों की कीमतों में मुद्रास्फीति कम रही।

विशेषकर लागत की मुद्रास्फीति फरवरी 2026 के बाद के निचले स्तर पर है। वहीं, उत्पादों की कीमतों में चार साल की सबसे सुस्त वृद्धि देखने को मिली। रिपोर्ट में कहा गया है कि नये कारोबार में वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण में भाग लेने वाली कंपनियों का कहना है कि मांग मजबूत बनी हुई है, नये ग्राहक बन रहे हैं और विपणन अभियानों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।

विदेशों से आने वाली मांग में बंगलादेश , कनाडा, इंडोनेशिया, नेपाल, ओमान, सऊदी अरब, श्रीलंका, ब्रिटेन, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात का सबसे अधिक योगदान रहा। मांग आने से कंपनियों ने अक्टूबर में उत्पादन बढ़ा दिया।

अच्छी मांग के बावजूद कारोबारी धारणा में गिरावट दर्ज की गई। सिर्फ 18 प्रतिशत कंपनियों ने कहा कि वे अगले एक साल में उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही हैं। वहीं, अन्य 82 प्रतिशत कंपनियों ने उत्पादन स्थिर रहने की बात कही है।



बचपन की फोटो वाली टी-शर्ट पहनकर अनन्या ने शनाया को किया बर्थडे विश



मुंबई। अभिनेता संजय कपूर और पत्नी महीप कपूर की लाडली और अभिनेत्री शनाया कपूर सोमवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर उनकी बेस्ट फ्रेंड और अभिनेत्री अनन्या पांडे ने उन्हें बधाई दी। अभिनेत्री अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक मिरर सेल्फी शेयर की, जिसमें वह काली टी-शर्ट पहने नजर आ रही हैं, जिस पर छोटी शनाया की तस्वीर छपी है। उन्होंने इस कैजुअल आउटफिट के साथ बेज कलर का बॉटम और ब्राइट पिंक हैंडबैग कैरी किया है।

एक और सोशल मीडिया स्टोरी में अनन्या ने शनाया के बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक दिखाई। इसमें बर्थडे गर्ल ब्लैक ऑफ-शोल्डर आउटफिट में एक सिंगल कैंडल वाले केक की तरफ झुकती हुई नजर आईं। अपनी दोस्त को विश करते हुए अनन्या ने लिखा, ₹लव ऑफ माय लाइफ, हैप्पी बर्थडे माय शनाया पपाया।₹फोटो शेयर करते हुए अनन्या ने लिखा, 'बिना कहे बताओ कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है।'

बता दें, अनन्या और शनाया बचपन से ही करीबी दोस्त हैं। उनकी माताएं, भावना पांडे और महीप कपूर भी दशकों से अच्छी दोस्त हैं और उनके बीच गहरा बॉन्ड है।अभिनेता संजय कपूर ने भी बेटी शनाया को जन्मदिन की बधाई देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें शनाया के बचपन से लेकर अभी तक की बहुत सारी वीडियो शामिल हैं। संजय कपूर ने लिखा, 'जन्मदिन की बधाई हो, शनाया कपूर।'

शनाया कपूर ने वर्ष 2020 की फिल्म 'गुंजन सक्सेनाः द कारगिल गर्ल' में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था। इसके बाद वह नेटफ्लिक्स के लोकप्रिय रियलिटी शो 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' में भी नजर आई थीं। उनकी पहली फिल्म करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस की 'बेधड़क' घोषित की गई थी, लेकिन यह फिल्म प्री-प्रोडक्शन स्टेज पर ही टाल दी गई।शनाया ने अपना आधिकारिक अभिनय डेब्यू वर्ष 2025 में आई फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' से किया, जिसमें वे अभिनेता विक्रांत मैसी के साथ दिखाई दी थीं। फरवरी 2026 में उनकी दूसरी फिल्म 'तू या मैं' रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने आदर्श गौरव के साथ काम किया।

'वीडियो का मकसद जागरूकता फैलाना था'

दीपावली संदेश से जुड़े विवाद के बीच दीया मिर्जा की सफाई



मुंबई। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के प्रदूषण कम करने वाले जागरूकता अभियान में शामिल अभिनेत्री दीया मिर्जा के वीडियो को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इसी बीच दीया मिर्जा का वीडियो बीएमसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। इस पूरे विवाद के बीच अब दीया मिर्जा ने आईएएनएस को अपना बयान दिया है। दीया मिर्जा ने आईएएनएस से कहा, ''दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा की जीत का उत्सव है।

यह वीडियो लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया था, ताकि उन्हें अधिक स्वस्थ और सोच-समझकर त्योहार मनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। वायु प्रदूषण जनस्वास्थ्य से जुड़ा एक मुद्दा है और इसे कम करने की दिशा में किया गया हर प्रयास सभी के लिए बेहतर पर्यावरण की ओर एक कदम है।''दरअसल, मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच बीएमसी ने दीपावली से पहले लोगों को प्रदूषण कम करने के लिए जागरूक करने का अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत कुछ वीडियो जारी किए गए थे, जिनमें दीया मिर्जा के अलावा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे भी नजर आए थे। इन वीडियो के जरिए लोगों से पटाखों का इस्तेमाल कम करने और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए दीपावली मनाने की अपील की गई थी।

हालांकि, दीया मिर्जा का वीडियो सामने आने के बाद इस पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने अभिनेत्री के वीडियो पर आपत्ति जताई और कहा कि लोगों को दीपावली मनाने के तरीके के बारे में दीया मिर्जा से सीख लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय परंपराओं में दीपावली का खास महत्व है और लोगों को अपने त्योहारों के बारे में अच्छी तरह पता है।विवाद बढ़ने के बाद बीएमसी ने दीया मिर्जा का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया। हालांकि, निगम की ओर से वीडियो हटाने की कोई सार्वजनिक वजह नहीं बताई गई।

बीएमसी के 'प्रदूषण मुक्त दीपावली' अभियान के बीच कोएना का पलटवार



मुंबई। अभिनेत्री कोएना मित्रा ने दीपावली पर पटाखे फोड़ने का समर्थन किया है और इसे त्योहार के पारंपरिक उल्लास का हिस्सा बताया। अभिनेत्री का कहना है कि हिंदू त्योहारों को कैसे मनाया जाए, इस पर दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं है।

अभिनेत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'सभी को मेरा नमस्कार, हम दीपावली रोशनी, पटाखों, संगीत, ढोल और स्वादिष्ट खाने के साथ मनाते हैं। हमें यह बताने के लिए पाकिस्तान के चमचों को मत बुलाइए कि हिंदू त्योहार कैसे मनाना चाहिए। उनके दिखावटी समाज-सेवा को नजरअंदाज कीजिए। एडवांस में दीपावली की शुभकामनाएं।'

उनका यह बयान उन लोगों और कथित बुद्धिजीवियों के खिलाफ एक सीधी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जो दीपावली के दौरान पर्यावरण और प्रदूषण का हवाला देकर पटाखे न फोड़ने या हिंदू त्योहारों पर रोक लगाने की वकालत कर रहे हैं।दरअसल, बीएमसी ने दीपावली के अवसर पर प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया था, जिसके तहत अभिनेत्री दीया मिर्जा का एक वीडियो संदेश जारी किया गया था। इस वीडियो में दीया मिर्जा ने मुंबईवासियों से अपील की थी कि वे पटाखे न जलाएं तथा ध्वनि और वायु प्रदूषण को कम करके एक पर्यावरण-अनुकूल दीपावली मनाएं।

उनका वीडियो सामने आने के बाद विवाद को हवा मिल गई। राजनीतिक और मनोरंजन जगत से प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा, 'मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। ये परेशानियां पूरे भारत में देखने को मिलती हैं।

विदेश

ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में वीकेंड पर सड़क हादसा

विक्टोरिया। साउथ-ईस्ट मेलबर्न में कार और बाइक की टक्कर में दो और लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस हादसे के बाद विक्टोरिया राज्य में वीकेंड पर सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या आठ हो गई।

बांग्लादेश में वेतन बढ़ाने की मांग पर कपड़ा श्रमिकों का उग्र प्रदर्शन

ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में कपड़ा श्रमिकों का आंदोलन उग्र हो गया है। न्यूनतम मासिक वेतन 30,000 टका करने की मांग को लेकर सोमवार को हजारों श्रमिकों ने प्रमुख राजमार्गों को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया।

अमेरिकी मिडटर्म चुनावः राष्ट्रपति की पार्टी के लिए क्यों है ये 'लिटमस टेस्ट', इतिहास में छुपा है जवाब



वाशिंगटन। अमेरिका में 3 नवंबर को मिडटर्म पोल यानि मध्यावधि चुनाव के लिए वोटिंग है। ऐसा चुनाव जिसमें राष्ट्रपति की कुर्सी तो नहीं खिसकती लेकिन उसके लिए खतरे की घंटी जरूर होता है। अमेरिका में मिडटर्म चुनाव को अक्सर राष्ट्रपति के कामकाज का लिटमस टेस्ट होता है। ये जनता की राय का पैमाना माना जाता है। अमेरिकी इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं, जब मिडटर्म चुनाव के नतीजों ने राष्ट्रपति को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर किया। वर्ष 1994, 2006 और 2010 के चुनाव इसके तीन बड़े उदाहरण हैं।

इन चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी को नुकसान होने का मतलब केवल कांग्रेस में सीटें कम होना नहीं, बल्कि इससे व्हाइट हाउस की सियासी ताकत, नीतियों और अगले दो वर्षों के एजेंडे पर भी असर पड़ता है।पहला बड़ा राजनीतिक झटका 1994 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को लगा था। उनके कार्यकाल के शुरुआती दो वर्षों में अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सुधार की योजना और प्रशासन के फैसलों को लेकर असंतोष बढ़ रहा था।

रिपब्लिकन पार्टी ने न्यूट गिंगरिच के नेतृत्व में 'कॉन्ट्रैक्ट विद अमेरिका' नाम से दस सूत्रीय एजेंडा पेश किया। इसमें करों में कटौती, सरकारी खर्च पर नियंत्रण और कल्याणकारी योजनाओं में बदलाव जैसे वादे शामिल थे। चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में 54 और सीनेट में आठ सीटों का इजाफा किया। इस जीत के साथ उसने करीब चार दशक बाद प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया।

इस नतीजे का असर जल्द ही दिखाई दिया। राष्ट्रपति क्लिंटन और रिपब्लिकन नेतृत्व के बीच बजट तथा सरकारी खर्च को लेकर टकराव बढ़ा। क्लिंटन ने रिपब्लिकन प्रस्तावों पर वीटो किया और बजट को लेकर गतिरोध इतना गहरा गया कि नवंबर और दिसंबर 1995 में अमेरिकी सरकार को दो बार कामकाज बंद करना पड़ा। इस दौरान लाखों संघीय कर्मचारियों के काम पर असर पड़ा और सरकारी सेवाएं भी बाधित हुईं। अंततः दोनों पक्षों को समझौते की राह पकड़नी पड़ी। यानी मिडटर्म में मिली जीत ने विपक्ष को कांग्रेस की कमान तो दी, लेकिन राष्ट्रपति के साथ टकराव ने पूरे देश के सरकारी कामकाज पर असर डाला।दूसरा अहम उदाहरण 2006 का है, जब राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश की रिपब्लिकन पार्टी को इराक युद्ध के मुद्दे पर जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी।

इराक हिंसा और अमेरिकी सैन्य अभियान की दिशा को लेकर सवाल उठ रहे थे। सात नवंबर को हुए मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में 30 और सीनेट में छह सीटें हासिल कीं। इस तरह रिपब्लिकन पार्टी ने दोनों सदनों में अपना बहुमत गंवा दिया।चुनाव का असर राष्ट्रपति के रक्षा विभाग तक पहुंचा। बुश प्रशासन की इराक नीति के प्रमुख चेहरों में शामिल रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने चुनाव के अगले दिन अपने पद से हटने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति ने उनकी जगह रॉबर्ट गेट्स को नियुक्त किया।

पाकिस्तान : लाहौर बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर

इस्लामाबाद। लाहौर को सोमवार को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 530 दर्ज किया गया और हवा में मौजूद बारीक कणों (पीएम2.5) की मात्रा 343 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई। आईक्यूएयर की सोमवार सुबह 9 बजे से 10 बजे तक की वैश्विक रैंकिंग के मुताबिक, लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जिसके बाद काहिरा का स्थान रहा जिसका वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 226 था।

डॉन अखबार के अनुसार, लाहौर के अलावा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अन्य शहर भी देश के सबसे प्रदूषित शहरी केंद्रों में शामिल थे।लाहौर 530 के एक्यूआई के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर रहा।

यमन में बंदरगाह और ऑयल फैसिलिटी पर सऊदी के हमलों में 7 घायलः हूती

सना। यमन के हूती गुट ने सोमवार को दावा किया कि सऊदी गठबंधन ने होदेइदाह प्रांत में लाल सागर का एक अहम बंदरगाह और ऑयल फैसिलिटी (तेल भंडारण केंद्र) को निशाना बनाया जिसमें सात लोग घायल हो गए।

दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक यमन में गृहयुद्ध फिर से भड़कने के बाद, ईरान समर्थित यह समूह सऊदी नेतृत्व वाले उस गठबंधन से लड़ रहा है, जो यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता है।हूती स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल-अस्बाही ने 'एक्स' पोस्ट के जरिए इन हमलों की जानकारी दी। बताया कि रविवार को रास इस्सा बंदरगाह पर सऊदी गठबंधन के हमलों में चार आम नागरिक घायल हुए, जबकि बाजील जिले में एक तेल सुविधा केंद्र पर हुए हमले में तीन अन्य लोग घायल हो गए।

नेपालः डोल्पा में बर्फबारी के बीच फंसे छह भारतीयों को किया गया रेस्क्यू



काठमांडू। पश्चिमी नेपाल के दूर-दराज जिले डोल्पा में भारी बर्फबारी के बीच फंसे छह भारतीय पर्यटकों को सोमवार सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। इलाके में बर्फबारी के कारण, 31 अक्टूबर से इन भारतीय पर्यटकों से संपर्क नहीं हो पा रहा था।डोल्पा स्थित जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) अनिल राज गिरी ने आईएएनएस को बताया, 'इनका पता चलने के बाद एक हेलीकॉप्टर भेजा गया और उन्हें जिले के मुख्यालय, दुनाई लाया गया।'

उन्होंने बताया कि बचाए गए सभी छह पर्यटकों की सेहत ठीक है।डीएसपी गिरी ने बताया कि ये पर्यटक खराब मौसम में फंस गए थे, जिसके बाद उन्हें शे-फोक्सुंडो ग्रामीण नगरपालिका के दानिगढ़ इलाके से सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह समूह धो तारांप से शे-फोक्सुंडो झील (जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है) की ओर ट्रेकिंग कर रहा था, तभी वे भारी बर्फबारी की चपेट में आ गए।अधिकारियों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि 31 अक्टूबर को इन पर्यटकों के फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद, उन्हें बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया।

हालांकि, खराब मौसम और हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने में आई दिक्कतों के कारण इस बचाव अभियान में विलंब हुआ।डीएसपी गिरी के अनुसार, ये भारतीय पर्यटक जरूरी प्रशासनिक परमिट लिए बिना ही अपर डोल्पा पहुंच गए थे। जिले का ऊपरी हिस्सा प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, वहां जाने वाले विदेशी नागरिकों को ट्रेकिंग परमिट जारी करने की जिम्मेदारी आव्रजन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन) की होती है।गिरी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात 'अर्नब' के कारण मौसम खराब हो रहा था, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों को इस इलाके में न जाने की चेतावनी दी थी।

27 अक्टूबर को, नेपाल के आव्रजन विभाग ने भारी बर्फबारी, बर्फीले तूफान और हिमस्खलन (एवलांच) के खतरे को देखते हुए, 29 से 31 अक्टूबर तक ऊंचे पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों के प्रतिबंधित इलाकों के लिए ट्रेकिंग परमिट जारी करना रोक दिया था।





